



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 27, 2010/फाल्गुन 8, 1931

No. 96]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 27, 2010/PHALGUNA 8, 1931

विदेश मंत्रालय

(सीपीवी प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2010

सा.का.नि. 168(अ).—जबकि भारत नाभिकीय पदार्थ भौतिक संरक्षण कन्वेंशन, 1980 का एक पक्षकार राज्य है जिसने 12 मार्च, 2002 को इसमें प्रवेश संबंधी दस्तावेज जमा किये हैं। भारत के लिए यह कन्वेंशन 11 अप्रैल, 2002 को लागू हुआ। भारत ने दिनांक 19 सितम्बर, 2007 को कन्वेंशन के 2005 के संशोधन का अनुसमर्थन भी किया है;

जबकि कन्वेंशन का अनुच्छेद 7 कतिपय कार्यों को दंडनीय अपराध के रूप में उपवर्णित करता है तथा पक्षकार राज्यों को इसके लिए बाध्य करता है कि वे उसे अपनी राष्ट्रीय विधियों के अंतर्गत दंडनीय बनायें;

जबकि अनुच्छेद 8.1 के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि पक्षकार राज्य उन अपराधों के ऊपर अधिकारिता स्थापित करें;

जबकि अनुच्छेद 11 के अनुसार उन अपराधों को पक्षकार राज्यों के बीच सभी वर्तमान एवं भावी प्रत्यर्पण संधियों में प्रत्यर्पणीय रूप में शामिल समझा जाता है;

जबकि पक्षकार राज्यों के बीच द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के अभाव में कन्वेंशन में उपवर्णित अपराधों के संबंध में प्रत्यर्पण हेतु कानूनी आधार विद्यमान है;

जबकि भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1992 की धारा 3 की उप-धारा (4) में निम्नलिखित व्यवस्था है : “जब भारत द्वारा किसी अन्य विदेशी राज्य के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, केन्द्रीय सरकार एक अधिसूचित आदेश द्वारा उस कन्वेंशन में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में प्रत्यर्पण हेतु भारत द्वारा उस विदेशी राज्य के साथ किये गये प्रत्यर्पण संधि के रूप में ऐसे किसी भी कन्वेंशन के संदर्भ ले सकती है जिसका भारत और एक विदेशी राज्य पक्षकार है।”

जबकि कन्वेंशन तथा संशोधन का पाठ यहां संलग्न है ;

संलग्नक:नाभिकीय पदार्थ भौतिक संरक्षण कन्वेंशन

इस समझौते के पक्षकार राज्य,

इस बात को मान्यता प्रदान करते हुए कि सभी राज्यों को शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु नाभिकीय ऊर्जा के विकास एवं अनुप्रयोग का अधिकार है तथा नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण अनुप्रयोग से मिलने वाले संभावित लाभों में उनका विधि सम्मत हित है,

यह स्वीकार करते हुए कि नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण अनुप्रयोग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुकर बनाने की जरूरत है,

इस इच्छा से कि नाभिकीय पदार्थ को गैर-कानूनी ढंग से ले जाने एवं उसके उपयोग से उत्पन्न संभावित खतरों को रोकना है,

यह स्वीकार करते हुए कि नाभिकीय पदार्थ से संबंधित अपराध गंभीर चिंता का विषय है तथा ऐसे अपराधों को रोकने, उनका पता लगाने एवं इस हेतु दंड की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए समुचित एवं प्रभावी उपायों को अंगीकार करने की तत्काल जरूरत है,

इस बात की जरूरत से अवगत होते हुए कि प्रत्येक पक्षकार राज्य के राष्ट्रीय कानून एवं इस कन्वेंशन के अनुरूप नाभिकीय पदार्थ के भौतिक संरक्षण हेतु प्रभावी उपाय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है,

यह स्वीकार करते हुए कि इस कन्वेंशन से नाभिकीय पदार्थ का सुरक्षित रूप से हस्तांतरण सुकर होगा, घरेलू उपयोग, भंडारण एवं परिवहन में नाभिकीय पदार्थ के भौतिक संरक्षण के महत्व पर भी बल देते हुए,

सैन्य प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त होने वाले नाभिकीय पदार्थ के प्रभावी भौतिक संरक्षण के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए तथा यह समझते हुए कि ऐसे पदार्थ को कड़े भौतिकी संरक्षण में रखा जाना है तथा सदैव रखना होगा,

निम्नलिखित रूप में सहमति व्यक्त करते हैं :

अनुच्छेद 1

इस कन्वेंशन के प्रयोजन हेतु :

- क. "नाभिकीय पदार्थ" से अभिप्रेत है, प्लूटोनियम- 80% से अधिक प्लूटोनियम 238 के आइसोटोपीय सांद्रण वाले प्लूटोनियम को छोड़कर यूरेनियम-233; आइसोटोप-235 या 233 से समृद्ध यूरेनियम; अयस्क या अयस्क अवशिष्ट रूप से भिन्न प्राकृतिक रूप से उपलब्ध आइसोटोप के मिश्रणयुक्त यूरेनियम; पूर्वोक्त में से एक या उससे अधिक पदार्थों से युक्त पदार्थ;

- ख. "आइसोटोप 235 या 233 से समृद्ध यूरेनियम" से अभिप्रेत है ऐसा यूरेनियम जिसमें आइसोटोप 235 या 233 या दोनों इस रूप में अंतर्विष्ट हों कि इन आइसोटोपों की कुल मात्रा एवं आइसोटोप 238 की पर्याप्तता का अनुपात प्राकृतिक रूप से प्राप्त आइसोटोप 235 एवं 238 के अनुपात से अधिक हो;
- ग. "अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय परिवहन" से अभिप्रेत है राज्य क्षेत्र के बाहर भेजे जाने हेतु किसी परिवहन माध्यम द्वारा उस स्थान से नाभिकीय पदार्थ के परेषण को ले जाना जहां से उसे जहाज पर लादा जाना हो । इसमें राज्य के पोत वणिग (शिपर) की सुविधा से उसका प्रस्थान भी शामिल है तथा इसकी परिणति गंतव्य राज्य के भीतर प्राप्तकर्ता की सुविधा में उसके पहुंचने पर होती है ।

अनुच्छेद 2

1. यह कन्वेंशन शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाये जाने वाले नाभिकीय पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय परिवहन के संबंध में लागू होगा ।
2. अनुच्छेद 3 एवं 4 और अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 3 के अपवादों को छोड़कर यह कन्वेंशन शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु नाभिकीय पदार्थ के घरेलू उपयोग, भंडारण एवं परिवहन हेतु भी लागू होगा ।
3. पैराग्राफ 2 में शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु नाभिकीय पदार्थ के घरेलू उपयोग, भंडारण एवं परिवहन के संबंध में समाहित अनुच्छेद में पक्षकार राज्यों द्वारा व्यक्त प्रतिबद्धता के अलावा इस कन्वेंशन में निहित किसी भी बात का निर्वचन इस रूप में नहीं किया जाएगा जो ऐसे नाभिकीय पदार्थ के घरेलू उपयोग, भंडारण एवं परिवहन के संबंध में एक राज्य के संप्रभु अधिकारों को प्रभावित करता हो ।

अनुच्छेद 3

प्रत्येक पक्षकार राज्य अपने राष्ट्रीय कानून के दायरे में तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप जहां तक व्यवहार्य हो यह सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त कदम उठायेगा कि अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय परिवहन के दौरान अपने क्षेत्र में नाभिकीय पदार्थ से लदे किसी पोत या हवाई जहाज को, जब तक वह पोत या हवाई जहाज उस संबंधित राज्य तक या वहां से उसके परिवहन में लगा है, संलग्नक-1 में वर्णित स्तरों पर उसको संरक्षा प्रदान की जाए ।

अनुच्छेद 4

1. प्रत्येक पक्षकार राज्य तब तक नाभिकीय पदार्थ का निर्यात नहीं करेगा या उसके निर्यात के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि पक्षकार राज्य को यह आश्वासन नहीं मिल जाता कि ऐसे पदार्थ को अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय परिवहन के दौरान संलग्नक-1 में वर्णित स्तर का संरक्षण प्रदान किया जाएगा ।
2. प्रत्येक पक्षकार राज्य किसी ऐसे राज्य से जो इस कन्वेंशन का पक्षकार नहीं है, तब तक नाभिकीय पदार्थ का आयात नहीं करेगा या उसके आयात के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि पक्षकार राज्य को यह

आश्वासन नहीं मिल जाता कि ऐसे पदार्थ को अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय परिवहन के दौरान संलग्नक- 1 में वर्णित स्तर का संरक्षण प्रदान किया जाएगा ।

3. कोई पक्षकार राज्य उन राज्यों के बीच अपने क्षेत्र में भूमि या आंतरिक जल मार्ग या अपने हवाई अड्डों या बंदरगाहों से नाभिकीय पदार्थ के परिवहन की अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक कि उस पक्षकार राज्य को यह आश्वासन नहीं मिल जाता कि ऐसे पदार्थ को अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय परिवहन के दौरान जहां तक व्यवहार्य है संलग्नक- 1 में वर्णित स्तर का संरक्षण प्रदान किया जाएगा ।
4. प्रत्येक पक्षकार राज्य अपने राष्ट्रीय कानून के दायरे में राज्य के एक हिस्से से उस राज्य के दूसरे हिस्से में अंतर्राष्ट्रीय जल या हवाई मार्ग से नाभिकीय पदार्थ के परिवहन के दौरान उसे संलग्नक-1 में वर्णित स्तर का भौतिक संरक्षण प्रदान करेगा ।
5. पैराग्राफ 1 से 3 तक के अनुसार संलग्नक- 1 में वर्णित स्तर का संरक्षण नाभिकीय पदार्थ को प्रदान करने का आश्वासन प्राप्त करने वाला पक्षकार राज्य अग्रिम रूप से उन राज्यों की पहचान करेगा जिनकी भूमि या अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों या हवाई मार्गों या बंदरगाहों में उसके प्रवेश या वहां से उसके गुजरने की आशा है तथा उन्हें इसकी सूचना अग्रिम रूप से देगा ।
6. पैराग्राफ 1 में उल्लिखित आश्वासन प्राप्त करने का उत्तरदायित्व पारस्परिक करार द्वारा आयातकर्ता राज्य, जो परिवहन में लगा है, को सौंपा जा सकता है ।
7. इस अनुच्छेद में किसी बात का निर्वचन इस रूप में नहीं किया जाएगा जिससे किसी भी प्रकार से किसी राज्य के हवाई क्षेत्र एवं प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र सहित उसकी प्रादेशिक संप्रभुता एवं अधिकारिता पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता हो ।

अनुच्छेद 5

1. पक्षकार राज्य एक दूसरे को सीधे या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के माध्यम से अपने उस केंद्रीय प्राधिकरण और संपर्क सूत्र की सूचना देंगे जिस पर नाभिकीय पदार्थ के भौतिक संरक्षण तथा नाभिकीय पदार्थ के अनधिकृत रूप से ले जाने, उसके उपयोग या उसमें परिवर्तन या विश्वसनीय रूप से उसे किसी प्रकार के खतरे की स्थिति में उसकी पुनर्प्राप्ति तथा जवाबी कार्रवाई करने का दायित्व है ।
2. नाभिकीय पदार्थ की चोरी, डकैती या अन्य किसी प्रकार से गैर-कानूनी ढंग से उसे ले जाने या इसके विश्वसनीय खतरे के मामले में पक्षकार राज्य अपने राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी राज्य द्वारा इसका अनुरोध किये जाने पर उसे उस पदार्थ की पुनर्प्राप्ति तथा संरक्षण में जहां तक संभव हो आवश्यक सहयोग एवं सहायता प्रदान करेंगे ।

- क. एक पक्षकार राज्य यथा संभव शीघ्रता से संबंधित दूसरे राज्यों को नाभिकीय पदार्थ की किसी चोरी, डकैती या अन्य कोई गैर-कानूनी ढंग से उसे ले जाने के संबंध में या इसके विश्वसनीय खतरे के संबंध में सूचित करेगा और जहां उचित हो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी इसकी सूचना देगा ।
- ख. संबंधित पक्षकार राज्य एक दूसरे के साथ या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समुचित रूप से सूचना का आदान-प्रदान करेंगे ताकि खतरे में पड़े नाभिकीय पदार्थ को संरक्षण प्रदान किया जा सके तथा उसके शिपिंग कंटेनर की अखण्डता को सुनिश्चित किया जा सके या गैर-कानूनी ढंग से ले जाया जा रहे नाभिकीय पदार्थ की पुनर्प्राप्ति की जा सके तथा वे;
- i. राजनयिक एवं अन्य मान्य चैनलों से अपने प्रयासों को समन्वित करेंगे;
 - ii. यदि अनुरोध किया जाए तो सहायता उपलब्ध करायेंगे;
 - iii. उपरोक्त कार्रवाईयों के माध्यम से चोरी हुए या खोये हुए नाभिकीय पदार्थ की वापसी को सुनिश्चित करेंगे;

इस सहयोग के क्रियान्वयन के साधनों के बारे में संबंधित पक्षकार राज्यों द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।

3. पक्षकार राज्य समुचित रूप में एक-दूसरे के साथ सीधे या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से सहयोग एवं परामर्श करेंगे ताकि अंतर्राष्ट्रीय परिवहन में नाभिकीय पदार्थ के भौतिक संरक्षण की प्रणाली के अभिकल्प, अनुरक्षण एवं विकास के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके ।

अनुच्छेद 6

1. पक्षकार राज्य अपने राष्ट्रीय कानून के अनुरूप इस कन्वेंशन के प्रावधानों के अंतर्गत दूसरे पक्षकार राज्य से या इस समझौते के क्रियान्वयन के लिए की गई किसी कार्रवाई में सहभागिता के माध्यम से प्राप्त किसी गोपनीय सूचना की गोपनीयता की रक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाएंगे । यदि पक्षकार राज्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को गोपनीय रूप से सूचना उपलब्ध कराते हैं तो ऐसी सूचना की गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जाएंगे ताकि उसकी रक्षा की जा सके ।
2. इस कन्वेंशन के अंतर्गत पक्षकार राज्यों से ऐसी सूचनाएं देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जिनको राष्ट्रीय कानून के अनुसार बताने की अनुमति नहीं है या जिनके कारण संबंधित राज्य या नाभिकीय पदार्थ के भौतिक संरक्षण की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है ।

अनुच्छेद 7

1. साभिप्राय किये गये कार्य में निम्नलिखित शामिल हैं :

क. बिना कानूनी प्राधिकार के नाभिकीय पदार्थ की प्राप्ति, उसे अपने कब्जे में रखना, उसका उपयोग, हस्तांतरण, रूपांतरण, निपटान या विसरण करना तथा उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु होना या उसे गहरी क्षति पहुंचाना या इसकी संभावना या किसी संपत्ति को उल्लेखनीय रूप से नुकसान पहुंचाना;

ख. नाभिकीय पदार्थ की चोरी या डकैती;

ग. नाभिकीय पदार्थ का गबन या उसे कपटपूर्ण ढंग से प्राप्त करना;

घ. धमकी या बल प्रयोग या अन्य किसी रूप में राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या नाभिकीय पदार्थों की रक्षा करने का कार्य ।

ज.

i. किसी व्यक्ति को भारी क्षति या गंभीर रूप से क्षति पहुंचाने या किसी संपत्ति को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने हेतु नाभिकीय पदार्थ के उपयोग या

ii. उप पैराग्राफ (ख) में वर्णित कोई ऐसा अपराध करने की धमकी देना जिससे एक स्वाभाविक या कानूनी व्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या राज्य को कोई कार्य करने या उससे विरत रहने के लिए बाध्य किया जा सके ।

च. पैराग्राफ (क), (ख) या (ग) में वर्णित कोई अपराध करने का प्रयास करना तथा

छ. पैरा (क) से (च) में वर्णित किसी अपराध में शामिल होने संबंधी किसी कार्य को

प्रत्येक पक्षकार राज्य द्वारा अपने राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध करार दिया जाएगा ।

2. प्रत्येक पक्षकार राज्य इस अनुच्छेद में वर्णित अपराधों के लिए समुचित दंड की व्यवस्था कर उसे दंडनीय करार देगा जिसमें उस अपराध के स्वरूप की गंभीरता को ध्यान में रखा जाएगा ।

अनुच्छेद 8

1. प्रत्येक पक्षकार राज्य निम्नलिखित मामलों में अनुच्छेद 7 में निर्धारित अपराधों पर अपनी अधिकारिता को स्थापित करने के लिए यथावश्यक कदम उठायेगा;
 - क. जब अपराध उस राज्य क्षेत्र में या उस राज्य क्षेत्र के पंजीकृत पोत या हवाई जहाज पर हुआ हो;
 - ख. जब अभिकथित अपराधी उस राज्य की राष्ट्रीयता वाला हो ।
2. इसी प्रकार प्रत्येक पक्षकार राज्य जिसके क्षेत्र में अभिकथित अपराधी विद्यमान हो, इन अपराधों पर अपनी अधिकारिता को स्थापित करने हेतु यथावश्यक कदम उठायेगा और वह अनुच्छेद 11 के अनुसरण में उन्हें पैराग्राफ 1 में उल्लिखित किसी राज्य को प्रत्यर्पित नहीं करेगा ।
3. इस समझौते में राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रयोग में लाये गये किसी दांडिक अधिकारिता को बाहर नहीं माना गया है ।
4. पैराग्राफ 1 एवं 2 में उल्लिखित पक्षकार राज्यों के अतिरिक्त उस प्रत्येक पक्षकार राज्य द्वारा जो निर्यातकर्ता या आयातकर्ता राज्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय परिवहन में संलग्न है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप अनुच्छेद 7 में निर्धारित अपराधों के संबंध में अपनी अधिकारिता स्थापित की जा सकती है ।

अनुच्छेद 9

पक्षकार राज्य, जिसके प्रदेश में अभिकथित अपराधी विद्यमान है, परिस्थितियों के अनुसार संतुष्ट होने पर उसके अभियोजन या प्रत्यर्पण के प्रयोजन हेतु उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने, जिसमें उसको रोक रखना भी शामिल है, के लिए अपने राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुचित उपाय करेगा । इस अनुच्छेद के अनुसार किए गए उपायों की सूचना अविलंब उन राज्यों को दी जाएगी जिन्हें अनुच्छेद 8 के अनुसरण में अधिकारिता स्थापित करने की अपेक्षा की जाती है तथा जहां उचित होगा इसकी सूचना सभी संबंधित अन्य राज्यों को भी दी जाएगी ।

अनुच्छेद 10

वह पक्षकार राज्य जिसके प्रदेश में अभिकथित अपराधी विद्यमान है, यदि उसे प्रत्यर्पित नहीं करता है तो उसे उस राज्य के कानूनों के अनुसार की जाने वाली कार्रवाहियों के माध्यम से अभियोजन के प्रयोजन हेतु बिना किसी अपवाद के तथा बिना किसी अनुचित विलंब के अपने सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष उसके मामले को प्रस्तुत करेगा ।

अनुच्छेद 11

1. अनुच्छेद 7 के अंतर्गत लिखित अपराधों को पक्षकार राज्यों के बीच वर्तमान किसी प्रत्यर्पण संधि में प्रत्यर्पणीय अपराधों के रूप में शामिल हुआ माना जाएगा । पक्षकार राज्य इसका वचन देते हैं कि उनके बीच संपन्न होने वाली प्रत्येक भावी प्रत्यर्पण संधि में उन अपराधों को प्रत्यर्पणीय अपराधों के रूप में शामिल किया जाएगा ।

21. यदि एक पक्षकार राज्य किसी संधि के आधार पर प्रत्यर्पण हेतु कोई शर्त रखता है और दूसरे पक्षकार राज्य किसी राज्य को कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, से प्रत्यर्पण का अनुरोध प्राप्त करता है तो वह अपने विचारों के समयांतर अपराधों के वर्गीकरण में प्रत्यर्पण हेतु इस कन्वेंशन को एक कानूनी आधार मान सकता है ।
22. जिस राज्य से प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है उसके कानूनों में उपलब्ध अन्य शर्तों के अधीन होगा ।
23. जो पक्षकार राज्य किसी वर्तमान संधि के आधार पर प्रत्यर्पण को सशर्त नहीं बनाते हैं वे उन अपराधों को अपने बीच प्रत्यर्पणीय अपराधों के रूप में मान्यता देंगे बशर्ते कि वह, जिस राज्य से अनुरोध किया गया है उसके कानूनों में उपलब्ध शर्तों के अधीन हो ।
24. पक्षकार राज्यों के बीच प्रत्यर्पण के प्रयोजन हेतु प्रत्येक अपराध को इस रूप में माना जाएगा, जैसे यह केवल उसी स्थान पर किया गया नहीं है जहां वह घटित हुआ है, बल्कि उन पक्षकार राज्यों के प्रदेश में भी घटित हुआ माना जाएगा जिनसे अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 1 के अनुसार अपनी अधिकारिता की स्थापना की अपेक्षा की जाती है ।

अनुच्छेद 12

अनुच्छेद 7 में उल्लिखित अपराधों में से किसी के संबंध में, किसी व्यक्ति के संबंध में की जा रही कार्यवाहियों के संबंध में कार्यवाहियों के सभी स्तरों पर निष्पक्ष व्यवहार की गारंटी दी जाएगी ।

अनुच्छेद 13

अनुच्छेद 7 में उल्लिखित अपराधों के संबंध में की जाने वाली आपराधिक कार्यवाहियों के संबंध में पक्षकार राज्य एक-दूसरे को अधिकतम सहायता प्रदान करेंगे जिनमें कार्यवाहियों हेतु उनके पास उपलब्ध आवश्यक साक्ष्य भी उपलब्ध कराना शामिल होगा । सभी मामलों में उस राज्य का कानून लागू होगा जिससे इसके लिए अनुरोध किया गया है ।

पैराग्राफ 1 के प्रावधान किसी अन्य द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधि में निहित उन बाध्यताओं को प्रभावित नहीं करेंगे, जिनसे आपराधिक मामलों में पारस्परिक सहायता पूर्णतः या आंशिक रूप से शासित होती हो या शासित होगी ।

अनुच्छेद 14

प्रत्येक पक्षकार राज्य इस कन्वेंशन को प्रभावी बनाने वाले अपने कानूनों एवं विनियमों की सूचना निक्षेपक(डिपॉजिटरी) को देगा । निक्षेपक(डिपॉजिटरी) आवधिक रूप से ऐसी सूचना सभी पक्षकार राज्यों को सम्प्रेषित करेगा ।

2. पक्षकार राज्य, जहां अभिकथित अपराधी को अभियोजित किया जा रहा है, जहां तक व्यवहार्य हो कार्यवाहियों के अंतिम निष्कर्ष की सूचना सबसे पहले सीधे संबंधित राज्यों को देगा। पक्षकार राज्य भी निक्षेपक(डिपाजिटरी) को अंतिम निष्कर्ष की सूचना देगा जो इसकी सूचना सभी राज्यों को देगा।
3. यदि कोई ऐसा अपराध होता है जिसमें घरेलू उपयोग, भंडारण या परिवहन में शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु नाभिकीय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है तथा अभिकथित अपराधी एवं नाभिकीय पदार्थ दोनों उस पक्षकार राज्य के क्षेत्र में ही विद्यमान हैं जिसमें अपराध हुआ है, तो इस कन्वेंशन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे ऐसे अपराध के फलस्वरूप की जाने वाली आपराधिक कार्यवाहियों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के लिए पक्षकार राज्य को बाध्य करने के लिए प्रतिपादित किया जाए।

अनुच्छेद 15

सभी संलग्नक इस कन्वेंशन के अभिन्न अंग हैं।

अनुच्छेद 16

1. इस कन्वेंशन के लागू होने के पांच वर्षों के उपरांत इस कन्वेंशन के क्रियान्वयन एवं इसकी प्रस्तावना, इसके सभी प्रचालनीय अंग एवं संलग्नकों की उस समय वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में पुनर्विलोकन के लिए पक्षकार राज्यों का एक सम्मेलन बुलाया जाएगा।
2. इसके उपरांत कम से कम पांच वर्षों के अंतराल पर पक्षकार राज्यों के बहुमत द्वारा इस संबंध में निक्षेपक(डिपाजिटरी) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर इसी उद्देश्य से आगे सम्मेलनों का आयोजन किया जा सकता है।

अनुच्छेद 17

1. दो या अधिक पक्षकार राज्यों के बीच इस कन्वेंशन के प्रतिपादन या अनुप्रयोग से संबंधित विवाद की स्थिति में संबंधित पक्षकार राज्य वार्ताओं द्वारा विवाद के निपटान की दृष्टि से या विवाद से संबंधित सभी पक्षकारों द्वारा विवाद के निपटान हेतु स्वीकार्य शांतिपूर्ण अन्य साधनों द्वारा परामर्श करेंगे।
2. इस प्रकार के किसी विवाद को, जो पैराग्राफ 1 में निर्धारित विधि से निपटाया नहीं जा सकता, ऐसे विवाद के किसी पक्षकार के अनुरोध पर, निर्णय हेतु माध्यस्थम (आर्बिट्रेशन) या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को भेजा जाएगा। जब कोई विवाद माध्यस्थम के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो यदि इस अनुरोध की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर विवाद से संबंधित पक्षकार माध्यस्थम द्वारा दी गई व्यवस्था पर सहमत नहीं हो पाते हैं तो कोई पक्षकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष (प्रेसीडेंट) या संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से एक या अधिक माध्यस्थम नियुक्त करने का अनुरोध कर सकता है। विवाद के पक्षकारों द्वारा परस्पर विरोधी अनुरोध करने के मामले में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से किये गये अनुरोध को प्राथमिकता दी जाएगी।

3. प्रत्येक पक्षकार राज्य इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर, इसके अनुसमर्थन, स्वीकृति या अनुमोदन या इसमें शामिल होने के समय पैराग्राफ-2 में दी गई विवाद निपटान की किसी एक या दोनों क्रियाविधि से अपने आबद्ध नहीं होने की घोषणा कर सकता है। यदि एक पक्षकार राज्य द्वारा किसी क्रियाविधि के संबंध में प्रारक्षण (रिजर्वेशन) व्यक्त किया गया है तो उसके संबंध में अन्य पक्षकार राज्य पैराग्राफ-2 में उपलब्ध विवाद निपटान क्रियाविधि से आबद्ध नहीं रहेंगे।
4. यदि किसी पक्षकार राज्य ने पैराग्राफ-3 के अनुसार प्रारक्षण (रिजर्वेशन) व्यक्त किया है तो किसी भी समय निक्षेपक (डिपोजिटरी) को अधिसूचित कर वह उसे वापस ले सकता है।

अनुच्छेद 18

1. यह कन्वेंशन दिनांक 3 मार्च 1980 से इसके लागू होने तक वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुख्यालय में तथा न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में सभी राज्यों के हस्ताक्षर के लिए रखा जाएगा।
 2. यह कन्वेंशन हस्ताक्षरकर्ता राज्यों द्वारा अनुसमर्थन, स्वीकृति या अनुमोदन के अधीन है।
 3. यह कन्वेंशन लागू होने के उपरांत सभी राज्यों के प्रवेश हेतु खुला रहेगा।
- क. यह कन्वेंशन संघटन या अन्य प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, तथा क्षेत्रीय संगठनों, बशर्ते कि ऐसे कोई संगठन संप्रभु राज्यों द्वारा गठित हो तथा इस कन्वेंशन में समाहित विषयों में अंतर्राष्ट्रीय करार पर वार्ता करने, निष्कर्ष निकालने तथा अनुप्रयोग के संबंध में सक्षम हो, के हस्ताक्षर या प्रवेश के लिए खुला रहेगा।
- ख. अपने सामर्थ्य के मामलों के भीतर ऐसे संगठन अपनी ओर से उन अधिकारों का प्रयोग करेंगे तथा उत्तरदायित्वों को पूरा करेंगे जो कन्वेंशन द्वारा पक्षकार राज्यों को सौंपे जाते हैं।
- ग. इस कन्वेंशन का एक पक्षकार बन जाने पर ऐसे संगठन निक्षेपक (डिपोजिटरी) को इस बात का उल्लेख करते हुए एक घोषणा पत्र भेजेंगे कि कौन से राज्य इसके सदस्य हैं तथा इस कन्वेंशन का कौन सा अनुच्छेद उनके ऊपर लागू नहीं होता है।
- घ. इस प्रकार के संगठन को इसके सदस्य राज्यों को प्राप्त मत (वोट) से कोई अतिरिक्त मत (वोट) प्राप्त नहीं होगा।

4. अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या प्रवेश के दस्तावेज निक्षेपक (डिपोजिटरी) के पास जमा किये जाएंगे।

अनुच्छेद 19

1. यह कन्वेंशन निक्षेपक के पास अनुसमर्थन, स्वीकृति या अनुमोदन के 21वें दस्तावेज के जमा होने की तिथि के बाद से 30वें दिन से लागू होगा।
2. अनुसमर्थन, स्वीकृति या अनुमोदन के 21वें दस्तावेज के जमा होने की तिथि के बाद से इस कन्वेंशन के अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन प्रदान करने वाले या इसमें प्रवेश करने वाले प्रत्येक राज्य के लिए यह कन्वेंशन उस राज्य द्वारा इसके अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या प्रवेश के दस्तावेज के जमा किये जाने के उपरांत 30वें दिन से लागू माना जाएगा।

अनुच्छेद 20

1. कोई पक्षकार राज्य अनुच्छेद 16 पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस कन्वेंशन में संशोधन का प्रस्ताव रख सकता है। प्रस्तावित संशोधन निक्षेपक के पास जमा किया जाएगा जो तत्काल सभी पक्षकार राज्यों को परिचालित करेगा। यदि पक्षकार राज्य बहुमत से प्रस्तावित संशोधन पर विचार करने के लिए निक्षेपक से सम्मेलन बुलाने का अनुरोध करते हैं तो निक्षेपक सभी पक्षकार राज्यों को ऐसे सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगा जो आमंत्रण पत्र जारी करने के बाद 30 दिनों से पहले नहीं आयोजित होगा। इस सम्मेलन में दो तिहाई बहुमत से अंगीकार किया गया कोई संशोधन तत्काल निक्षेपक द्वारा सभी पक्षकार राज्यों को परिचालित किया जाएगा।
2. प्रत्येक पक्षकार राज्य जिसने संशोधन के अनुसमर्थन, स्वीकृति या अनुमोदन के अपने दस्तावेज निक्षेपक के पास जमा किये हैं उनके लिए यह संशोधन दो तिहाई पक्षकार राज्यों द्वारा अपने अनुसमर्थन, स्वीकृति या अनुमोदन के दस्तावेज जमा किये जाने की तिथि के 30वें दिन से लागू होगा। तत्पश्चात् किसी अन्य पक्षकार राज्य के लिए यह संशोधन उसी दिन से लागू होगा जिस दिन उस पक्षकार राज्य ने संशोधन का अनुसमर्थन, स्वीकृति या अनुमोदन के अपने दस्तावेज जमा किये हैं।

अनुच्छेद 21

1. कोई पक्षकार राज्य निक्षेपक को लिखित रूप में एक अधिसूचना द्वारा इस कन्वेंशन से अलग हो सकता है।
2. कन्वेंशन से उसका अलग होना निक्षेपक द्वारा अधिसूचना प्राप्ति की तिथि के बाद से 180वें दिन से प्रभावी होगा।

अनुच्छेद 22

निक्षेपक सभी राज्यों को तत्काल निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करेगा:

- क. इस कन्वेंशन पर किए गए प्रत्येक हस्ताक्षर;
- ख. अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या प्रवेश के जमा किये गये प्रत्येक दस्तावेज़;
- ग. अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी शर्त या संधि से बाहर निकलना;
- घ. अनुच्छेद 18 के पैराग्राफ (ग) के अनुसार किसी संघटन द्वारा किया गया पत्राचार;
- ङ. इस कन्वेंशन के लागू होने के संबंध में;
- च. इस कन्वेंशन के किसी संशोधन के लागू होने; तथा
- छ. अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किया गया कोई प्रत्याख्यान (डिनाउन्सिएशन) ।

अनुच्छेद 23

इस कन्वेंशन की मूल प्रति, जिसका अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी एवं स्पेनिश पाठ भी समान रूप से प्रमाणिक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक के पास जमा की जाएगी जो उनकी प्रमाणित प्रतियां सभी राज्यों को भेजेंगे।

इसके साक्ष्य स्वरूप अधोहस्ताक्षरी ने विधिवत प्राधिकृत रूप में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये हैं, जो दिनांक 3 मार्च 1980 को विएना एवं न्यूयार्क में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था।

संलग्नक ।

संलग्नक-II में श्रेणीकृत रूप से नाभिकीय पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन में लागू किया जाने वाला भौतिक संरक्षण स्तर

1. अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय परिवहन की स्थिति में भंडारण के दौरान नाभिकीय पदार्थ हेतु भौतिक संरक्षण का स्तर :

- क. श्रेणी III के पदार्थों हेतु भंडारण ऐसे क्षेत्र में हो जिसमें प्रवेश नियंत्रित हो;

ख. श्रेणी II के पदार्थों हेतु भंडारण ऐसे क्षेत्र में हो जो अनवरत गार्डों या इलेक्ट्रानिक डिवाइसों की निगरानी के भीतर हो तथा समुचित नियंत्रण में प्रवेश के सीमित स्थल हो जिनके चारों ओर भौतिक अवरोध हो या उसके बराबर के स्तर का भौतिक संरक्षण वाला कोई क्षेत्र हो;

ग. श्रेणी I के पदार्थ का भंडारण उपरोक्त श्रेणी II हेतु परिभाषित रूप में संरक्षित क्षेत्र के भीतर हो तथा उसमें केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाए जो विश्वसनीय हों तथा जो उन गार्डों की निगरानी के अंतर्गत हो जो उपयुक्त जवाबी कार्यवाई बलों (रिस्पांस फोर्सों) से तेजी से संवाद स्थापित कर सकते हों। इस संदर्भ में विशिष्ट उपायों के रूप में उनका लक्ष्य किसी हमले का पता लगाना एवं उनको रोकना, किसी अनधिकृत प्रवेश को रोकना या पदार्थ को अनधिकृत रूप से जाना से रोकना होना चाहिए।

2. अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय परिवहन के दौरान नाभिकीय पदार्थ हेतु भौतिक संरक्षण का स्तर :

क. श्रेणी II और श्रेणी III के पदार्थों के लिए परिवहन में विशेष सावधानी बरती जाएगी जिसकी पूर्व व्यवस्थाएं प्रेषक, प्राप्तकर्ता एवं वाहक के बीच की जाएंगी तथा परिवहन के उत्तरदायित्व के हस्तांतरण हेतु समय, स्थान एवं क्रियाविधियों का उल्लेख करते हुए निर्यात एवं आयातकर्ता राज्यों की अधिकारिता एवं विनियम के अधीन स्वाभाविक तथा कानूनी व्यक्तियों के बीच पूर्व करार संपन्न किया जाएगा।

ख. श्रेणी-I के पदार्थों का परिवहन में श्रेणी-II एवं III के पदार्थों के परिवहन हेतु बतायी गयी उपरोक्त सावधानियां बरती जाएंगी तथा इसके अतिरिक्त वे लगातार अभिरक्षकों (एस्कॉर्ट्स) की निगरानी में रहेंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपयुक्त जवाबी कार्यवाई बलों (रिस्पांस फोर्सों) के साथ उनका निकट से संचार संपर्क बना रहे।

ग. अयस्क या अयस्क अवशिष्ट से भिन्न प्राकृतिक यूरेनियम के लिए 500 किलोग्राम यूरेनियम से अधिक मात्रा हेतु दिये जाने वाले परिवहन संरक्षण में उसके जहाज में लदान (शिपमेंट) को अग्रिम रूप से अधिसूचित किया जाएगा जिसमें उसके परिवहन की विधि, उसके पहुंचने का अनुमानित समय तथा लदान (शिपमेंट) के लिए पावती की अभिपुष्टि शामिल होगी।

संलग्नक-II

सारणी: नाभिकीय पदार्थों का श्रेणीकरण

पदार्थ	रूप	श्रेणी		
		I	II	III ^{सी/}
1. प्लूटोनियम ^{ए/}	अकिरणित ^{सी/}	2 किग्रा या अधिक	2 किग्रा से कम] पर 500 ग्राम से अधिक	500 ग्राम या कम] पर 15 ग्राम से अधिक
2. यूरेनियम- 235	अकिरणित ^{सी/} <ul style="list-style-type: none"> • 20%^{235यू} या अधिक समृद्ध यूरेनियम • 10%^{235यू} लेकिन 20% से कम समृद्ध यूरेनियम, • प्राकृतिक से अधिक समृद्ध यूरेनियम, पर 10%^{235यू} से कम 	5 किग्रा या अधिक	5 किग्रा से कम] पर 1 किग्रा से अधिक 10 किग्रा या अधिक	1 किग्रा या कम] पर 15 ग्राम से अधिक 10 किग्रा से कम] पर 1 किग्रा से अधिक 10 किग्रा या अधिक
3. यूरेनियम- 233	अकिरणित ^{सी/}	2 किग्रा या अधिक	2 किग्रा से कम पर 500 ग्राम से अधिक	500 ग्राम या कम] पर 15 ग्राम से अधिक
4. किरणित ईंधन			अवक्षयित या प्राकृतिक यूरेनियम, थोरियम या निम्न समृद्ध ईंधन (10% से कम जीवाश्म अंशयुक्त) ^{डी/ई/}	

- ^{ए/} 80% से अधिक प्लूटोनियम 238 के आइसोटोपीय सांद्रण वाले प्लूटोनियम को छोड़कर सभी प्लूटोनियम
- ^{बी/} रिएक्टर में किरणित पदार्थ या रिएक्टर में अकिरणित पदार्थ लेकिन 1 मीटर की अपरिरक्षित दूरी पर 100
- ^{सी/} रैंड्स/प्रतिघंटे के बराबर या उससे कम स्तर के विकिरण सहित
- ^{डी/} जो मात्रा श्रेणी-III के अंतर्गत नहीं समाहित है तथा प्राकृतिक यूरेनियम को विवेक पूर्ण प्रबंधन विधि के अनुसार
- ^{ई/} संरक्षित किया जाना चाहिए।
- ^{फ/} हालांकि इस स्तर के संरक्षण की सिफारिश की जाती है तथापि राज्यों के लिए विशेष परिस्थितियों में इसका
- ^{जी/} मूल्यांकन कर इसे अलग श्रेणी का भौतिक संरक्षण प्रदान किये जाने का विकल्प खुला रहेगा।
- ^{एच/} 1 मीटर की अपरिरक्षित दूरी पर 100 रैंड्स/प्रतिघंटे से विकिरण स्तर बढ़ने पर किरणन के एक श्रेणी स्तर कम
- ^{आई/} हो जाने से पूर्व अन्य ईंधन को मूल विखंडनीय पदार्थ के अंश के कारण श्रेणी-I एवं श्रेणी-II में रखा जाता है।

नाभिकीय पदार्थ भौतिक संरक्षण कन्वेंशन में संशोधन

1. दिनांक 26 अक्टूबर 1979 को अंगीकार किए गए नाभिकीय पदार्थ भौतिक संरक्षण कन्वेंशन (इसमें इसके बाद "कन्वेंशन" के रूप में निर्दिष्ट) के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाता है :

नाभिकीय पदार्थ और नाभिकीय सुविधा भौतिक संरक्षण कन्वेंशन

2. कन्वेंशन की प्रस्तावना निम्नलिखित पाठ से प्रतिस्थापित की जाती है :

इस कन्वेंशन के पक्षकार राज्य,

इस बात को मान्यता प्रदान करते हुए कि सभी राज्यों को शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु नाभिकीय ऊर्जा के विकास एवं अनुप्रयोग का अधिकार है तथा नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण अनुप्रयोग से मिलने वाले संभावित लाभों में उनका विधि सम्मत हित है,

यह स्वीकार करते हुए कि नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण अनुप्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं नाभिकीय प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को सुकर बनाने की जरूरत है,

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जन स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के संरक्षण हेतु भौतिक संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा तथा राज्यों के बीच एक पड़ोसी के रूप में अच्छे एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों एवं सहयोग को बढ़ाने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के प्रयोजनों एवं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए,

इस बात को मानते हुए कि संयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्र के अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 4 के निबंधनों के अंतर्गत, "सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी राज्य की प्रादेशिक अखंडता के विरुद्ध धमकी देने या बल प्रयोग से बचेंगे या किसी अन्य रूप में संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों के प्रतिकूल नहीं जाएंगे"

महासभा (जनरल एसेंबली) के दिनांक 09 दिसंबर 1994 के संकल्प 49/60 से संलग्न अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को दूर करने हेतु उपायों संबंधी घोषणा का स्मरण करते हुए,

नाभिकीय पदार्थ के अवैध व्यापार, गैर-कानूनी ढंग से उसे ले-जाने एवं उसके उपयोग तथा नाभिकीय पदार्थ एवं नाभिकीय सुविधाओं के तोड़-फोड़ द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से बचने की इच्छा से तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे कार्यों के विरुद्ध भौतिक संरक्षण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय हो गया है,

विश्व स्तर पर खपत सभी रूपों में आतंकवाद तथा प्रत्यक्ष आतंकवादी कार्यों में वृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा संगठित अपराध द्वारा उत्पन्न खतरों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए,

इस बात में विश्वास करते हुए कि भौतिक संरक्षण नाभिकीय अप्रसार के समर्थन में एवं आतंकवादी उद्देश्यों का मुकाबला करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है,

शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु नाभिकीय पदार्थ एवं नाभिकीय सुविधाओं के विश्व स्तरीय भौतिक संरक्षण को और मजबूत करने में इस कन्वेंशन के माध्यम से योगदान करने की इच्छा से,

इस बात को स्वीकार करते हुए कि नाभिकीय पदार्थ से संबंधित अपराध गंभीर चिंता का विषय हैं तथा ऐसे अपराधों को रोकने, उनका पता लगाने एवं इस हेतु दंड की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त एवं प्रभावी उपायों या वर्तमान उपायों को और सशक्त करने की तत्काल जरूरत है,

प्रत्येक पक्षकार राज्य के राष्ट्रीय कानून एवं इस कन्वेंशन के अनुरूप नाभिकीय पदार्थ एवं नाभिकीय सुविधाओं के भौतिक संरक्षण हेतु प्रभावी उपाय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करने की इच्छा से,

इस बात को स्वीकार करते हुए कि यह कन्वेंशन नाभिकीय पदार्थ के सुरक्षित उपयोग, भंडारण एवं परिवहन में तथा नाभिकीय सुविधाओं के सुरक्षित प्रचालन में पूरक होगा,

इस बात को मान्यता प्रदान करते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से तैयार की गई भौतिक संरक्षण संबंधी ऐसी सिफारिशें, जिन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जाता है, विद्यमान हैं जो भौतिक संरक्षण के प्रभावी स्तरों को प्राप्त करने के समसामयिक साधनों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हैं,

इस बात को मान्यता प्रदान करते हुए कि सैन्य प्रयोजनों हेतु नाभिकीय पदार्थ एवं नाभिकीय सुविधाओं के प्रभावी भौतिक संरक्षण का उत्तरदायित्व उन राज्यों पर है जिनके यहां ऐसे नाभिकीय पदार्थ एवं नाभिकीय सुविधाएं विद्यमान हैं तथा यह समझते हुए कि ऐसे पदार्थ एवं सुविधाओं को कड़े भौतिकी संरक्षण में रखना है तथा रखना होगा,

निम्नलिखित पर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं :

3. कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 में पैराग्राफ (ग) के उपरान्त निम्न रूप में दो नए पैराग्राफ जोड़े जाते हैं :

(घ) "नाभिकीय सुविधाओं" से अभिप्रेत है वह सुविधा (संबद्ध भवनों एवं उपस्कर सहित) जिसमें नाभिकीय पदार्थ का उत्पादन, संसाधन, उपयोग, हस्तन, भंडारण या निपटान होता है और ऐसी सुविधा को कोई क्षति पहुंचने या व्यतिकरण से उल्लेखनीय मात्रा में विकिरण या विकिरण सक्रिय पदार्थ की निर्मुक्ति हो सकती है ;

(ङ) "तोड़-फोड़" से अभिप्रेत है किसी नाभिकीय सुविधा या उपयोग, भंडारण या परिवहन के दौरान नाभिकीय पदार्थ के विरुद्ध साभिप्राय किया गया कोई कार्य जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कार्मिकों, जनता या पर्यावरण को विकिरण या रेडियोसक्रिय पदार्थों की निर्मुक्ति के उद्भासन द्वारा खतरा उत्पन्न हो ।

4. कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 के उपरांत निम्नरूप में एक नया अनुच्छेद 1क जोड़ा जाता है :

इस कन्वेंशन का प्रयोजन शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाये जाने वाले नाभिकीय पदार्थ तथा शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु नाभिकीय सुविधाओं को विश्व स्तरीय प्रभावी भौतिक संरक्षण प्रदान करना तथा उसे बनाए रखना है ताकि पूरे विश्व में ऐसे पदार्थ एवं सुविधाओं से संबंधित अपराधों को रोका जा सके तथा उसका सामना किया जा सके; साथ ही इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पक्षकार राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ाया जा सके ।

5. कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 के स्थान पर निम्नलिखित पाठ रखा जाएगा :

1. यह कन्वेंशन शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाये जाने वाले नाभिकीय पदार्थों के उपयोग, भंडारण एवं परिवहन तथा शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु उपयोग में लायी जाने वाली नाभिकीय सुविधाओं पर लागू होगा बशर्ते कि तथापि, इस कन्वेंशन का अनुच्छेद 3 एवं 4 एवं अनुच्छेद 5 का पैराग्राफ 4 ऐसे नाभिकीय पदार्थ के संबंध में केवल अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय परिवहन के दौरान लागू होगा ।

2. एक पक्षकार राज्य के भीतर भौतिक संरक्षण व्यवस्था को स्थापित, क्रियान्वित करने तथा उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी पूर्णतया उस राज्य पर है ।

3. पक्षकार राज्यों द्वारा इस कन्वेंशन के अंतर्गत व्यक्त प्रतिबद्धताओं के अलावा इस कन्वेंशन की किसी भी बात का निर्वचन इस रूप में नहीं किया जाएगा जो एक राज्य के संप्रभु अधिकारों को प्रभावित करता हो ।

4.(क) इस कन्वेंशन की कोई भी बात अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत राज्यों को प्राप्त अन्य अधिकारों, बाध्यताओं एवं उत्तरदायित्वों, विशेषकर, संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के घोषणा-पत्र के प्रयोजनों एवं सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करेगी ।

(ख) एक सशस्त्र युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों की गतिविधियाँ, जैसाकि उन पदावलियों को अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के अंतर्गत समझा जाता है जो उस कानून से अधिशासित होती है, इस कन्वेंशन द्वारा नहीं तथा अपने अधिकारिक कर्तव्यों के निर्वाह में किसी राज्य के सैन्य बलों द्वारा की गई कार्रवाइयाँ, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य नियमों द्वारा शासित होती हैं, इस कन्वेंशन द्वारा शासित नहीं होती हैं ।

(ग) इस कन्वेंशन में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाये जाने वाले नाभिकीय पदार्थ या नाभिकीय सुविधाओं के विरुद्ध बल प्रयोग या उसके प्रयोग की धमकी देना कानूनी रूप से प्राधिकृत है ।

(घ) इस कन्वेंशन में ऐसी कोई बात नहीं है जो अन्यथा रूप में गैर कानूनी कार्रवाइयों को माफ करती है या कानूनी बनाती है और न ही उसे अन्य कानूनों के अंतर्गत अभियोजन से प्रतिबाधित करती है ।

5. यह कन्वेंशन सैन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाये गये या रखे गये नाभिकीय पदार्थ या नाभिकीय सुविधा जिसमें ऐसा पदार्थ विद्यमान है, के लिए लागू नहीं होगा ।

6. इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 के उपरांत निम्नरूप में एक नया अनुच्छेद 2 क जोड़ा जाता है :

अनुच्छेद 2 क

1. प्रत्येक पक्षकार राज्य अपने क्षेत्राधिकार के अधीन नाभिकीय पदार्थ एवं नाभिकीय सुविधाओं हेतु लागू होने वाली एक समुचित भौतिक संरक्षण व्यवस्था को स्थापित, क्रियान्वित करेगा एवं बनाए रखेगा, जिसका उद्देश्य होगा :

- (क) उपयोग, भंडारण, परिवहन के दौरान नाभिकीय पदार्थ की चोरी तथा अन्य गैर-कानूनी ढंग से उसे ले जाने से उसकी रक्षा करना;
- (ख) चोरी हुए नाभिकीय पदार्थ का पता लगाने एवं जहाँ उचित हो उस खोये हुए या चोरी गए नाभिकीय पदार्थ को उनकी पुनर्प्राप्ति हेतु तेजी से तथा व्यापक स्तर पर उपायों के क्रियान्वन को सुनिश्चित करना;
- (ग) तोड़-फोड़ से नाभिकीय पदार्थों एवं नाभिकीय सुविधाओं को संरक्षण प्रदान करना तथा;
- (घ) तोड़-फोड़ के विकिरणकीय परिणामों को शमन या उन्हें कम करना ।

2. प्रत्येक पक्षकार राज्य पैराग्राफ 1 को क्रियान्वित करने हेतु :

- (क) भौतिक संरक्षण के लिए एक विधायी एवं नियामक संगठन की स्थापना करेगा तथा उसे बनाये रखेगा;
- (ख) विधायी तथा नियामक ढांचे को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी एक सक्षम प्राधिकरण या प्राधिकरणों की स्थापना करेगा या उसको पदनामित करेगा तथा
- (ग) नाभिकीय पदार्थ तथा नाभिकीय सुविधाओं के भौतिक संरक्षण हेतु आवश्यक अन्य समुचित उपाय करेगा ।

3. पैराग्राफ 1 एवं 2 के अंतर्गत बाध्यताओं को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक पक्षकार राज्य इस कन्वेंशन के किन्ही अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नाभिकीय पदार्थ एवं नाभिकीय सुविधाओं के भौतिक संरक्षण के निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांतों को जहां तक युक्तिसंगत हो तथा व्यवहार्य हो उस रूप में लागू करेगा ।

मूलभूत सिद्धांत क : राज्य का उत्तरदायित्व

एक राज्य के भीतर भौतिक संरक्षण व्यवस्था की स्थापना, उसके क्रियान्वयन एवं उसे बनाए रखने का उत्तरदायित्व पूर्णतया उस राज्य पर है ।

मूलभूत सिद्धांत ख : अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के दौरान उत्तरदायित्व

नाभिकीय पदार्थ के समुचित संरक्षण को सुनिश्चित करने का राज्य का उत्तरदायित्व तब तक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का है जब तक कि दूसरे राज्य को समुचित रूप से उसका उत्तरदायित्व हस्तांतरित नहीं कर दिया जाता ।

मूलभूत सिद्धांत ग : विधायी एवं नियामक संरचना

भौतिक संरक्षण को अधिशासित करने के लिए एक विधायी एवं नियामक संरचना की स्थापना एवं उसे बनाए रखने का उत्तरदायित्व राज्य का है । इस संरचना के अंतर्गत प्रयोज्य भौतिक संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए तथा इसमें मूल्यांकन तथा लाईसेंस जारी करने या प्राधिकृतीकरण प्रदान करने हेतु अन्य क्रिया विधियां शामिल होनी चाहिए । इस संरचना में नाभिकीय सुविधाओं एवं परिवहन के निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लाईसेंस या अन्य प्राधिकृतीकरण दस्तावेज की शर्तों एवं व्यवहार्य अपेक्षाओं के अनुपालन की जांच की जा सके तथा प्रयोज्य अपेक्षाओं तथा प्रभावी प्रतिबंधों सहित शर्तों को लागू करने के साधन स्थापित किए जा सकें ।

मूलभूत सिद्धांत घ : सक्षम प्राधिकरण

राज्य द्वारा एक ऐसे सक्षम प्राधिकरण की स्थापना या उसे पदनामित किया जाना चाहिए जो विधायी एवं नियामक संरचना को क्रियान्वित करने हेतु उत्तरदायी हो तथा उसे अपने सौंपे गये उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए समुचित अधिकार, क्षमता एवं वित्तीय एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए । राज्य के सक्षम प्राधिकरण तथा नाभिकीय ऊर्जा की अभिवृद्धि या उपयोगिता के प्रभावी किसी अन्य निकाय के बीच उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए ।

मूलभूत सिद्धांत ङ : लाइसेंसधारी का उत्तरदायित्व

एक राज्य के भीतर भौतिक संरक्षण के विभिन्न तत्वों को क्रियान्वित करने के उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित कर दिया जाना चाहिए। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नाभिकीय पदार्थ या नाभिकीय सुविधाओं के संरक्षण के क्रियान्वयन का मुख्य उत्तरदायित्व संबंधित लाइसेंसधारी या अन्य प्राधिकार प्रदानकर्ता उस्तावेजों के धारक (अर्थात्, आपरेटरों या पोत वणिकों [शिपर्स]) का है।

मूलभूत सिद्धांत च : सुरक्षा संस्कृति

भौतिक संरक्षण के क्रियान्वयन में लगे सभी संगठनों को, सुरक्षा संस्कृति, इसके विकास तथा अनुरक्षण को यथोचित प्राथमिकता देनी चाहिए जो संपूर्ण संगठन में इसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

मूलभूत सिद्धांत छ : खतरा

राज्य का भौतिक संरक्षण राज्य के खतरे के वर्तमान मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए।

मूलभूत सिद्धांत ज : श्रेणीकृत पहल

भौतिक संरक्षण संबंधी जरूरतें श्रेणीकृत पहल पर आधारित होनी चाहिए जिसमें खतरे का वर्तमान मूल्यांकन, आपेक्षिक आकर्षकता, पदार्थ के स्वरूप तथा नाभिकीय पदार्थ के अनधिकृत रूप से ले जाने तथा नाभिकीय पदार्थ तथा नाभिकीय सुविधाओं के विरुद्ध तोड़फोड़ से जुड़े संभावित परिणामों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मूलभूत सिद्धांत झ : सघन सुरक्षा

भौतिक संरक्षण के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य की आवश्यकताओं में (संरचनात्मक या अन्य तकनीकी, कार्मिक तथा संगठनात्मक) संरक्षण के उन सभी स्तरों एवं विधियों की संकल्पना प्रतिबिंबित होनी चाहिए जिन पर प्रतिकूल परिस्थितियों में विजय प्राप्त करनी है या जिनसे हम घिरने वाले हैं।

मूलभूत सिद्धांत ज : गुणवत्ता आश्वासन

यह विश्वासन पैदा करने के लिए कि भौतिक संरक्षण की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए विनिर्दिष्ट आवश्यकताएं पूरी कर ली गई हैं, एक गुणवत्ता आश्वासन नीति तथा गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम बना लिया जाने तथा क्रियान्वित कर लिया जाना चाहिए।

मूलभूत सिद्धांत ट : आपातकालीन योजनाएं

नाभिकीय पदार्थ के अनधिकृत रूप से ले जाने या नाभिकीय सुविधाओं या नाभिकीय पदार्थ के तोड़फोड़ या इसके प्रयासों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु एक आपातकालीन योजना तैयार की जानी चाहिए तथा सभी लाइसेंसधारियों एवं संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उसका समुचित रूप से अभ्यास किया जाना चाहिए।

मूलभूत सिद्धांत उ : गोपनीयता

राज्य द्वारा सूचनाओं की गोपनीयता की रक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए क्योंकि उनके अनधिकृत रूप से प्रकट हो जाने के परिणामस्वरूप नाभिकीय पदार्थ एवं नाभिकीय सुविधाओं को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

4. (क) इस अनुच्छेद के प्रावधान ऐसे किसी नाभिकीय पदार्थ पर लागू नहीं होंगे जिनके बारे में पक्षकार राज्य विवेक सम्मत रूप से पदार्थ के स्वरूप, उसकी मात्रा तथा आपेक्षिक आकर्षकता तथा उसके विरुद्ध निर्देशित किसी अनधिकृत कार्य से संबद्ध संभावित विकिरणकीय एवं अन्य परिणामों तथा इसके विरुद्ध वर्तमान खतरे के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लेता है कि पैराग्राफ-1 के अनुसरण में स्थापित भौतिक संरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें रखने की जरूरत नहीं है।

(ख) जो नाभिकीय पदार्थ उप पैराग्राफ "क" के अनुसरण में इस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें व्यक्तिपूर्ण प्रबंधन नियमों के अनुसार संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

7. इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 5 के स्थान पर निम्नलिखित पाठ रखा जाता है :

1. पक्षकार राज्य इस कन्वेंशन के क्षेत्र के भीतर के विषयों के संबंध में अपने केंद्रीय प्राधिकरण का निर्धारण कर सीधे या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के माध्यम से उसकी सूचना एक दूसरे को देंगे।
2. नाभिकीय पदार्थ की चोरी, डकैती या अन्य किसी प्रकार से गैर-कानूनी ढंग से उसे ले जाने या इसके विश्वसनीय खतरे के मामले में पक्षकार राज्य अपने राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी राज्य द्वारा इसका अनुरोध

किये जाने पर उस पदार्थ की पुनर्प्राप्ति तथा संरक्षण में जहां तक संभव हो आवश्यक सहयोग एवं सहायता प्रदान करेंगे ।

क. कोई पक्षकार राज्य यथा संभव शीघ्रता से संबंधित दूसरे राज्यों को नाभिकीय पदार्थ या किसी चोरी, डकैती या अन्य किसी गैर-कानूनी ढंग से उसे ले जाने के संबंध में या इसके विश्वसनीय खतरे के संबंध में सूचित करेगा और जहां उचित हो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी इसकी सूचना देगा ।

ख. ऐसा करने समय जैसा उचित समझा जाए, संबंधित पक्षकार राज्य एक दूसरे के साथ, या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी तथा अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करेंगे ताकि खतरे में पड़े नाभिकीय पदार्थ को संरक्षण प्रदान किया जा सके तथा उसके शिपिंग कंटेनर की अखण्डता को सुनिश्चित किया जा सके या गैर-कानूनी ढंग से ले जाया जा रहे नाभिकीय पदार्थ की पुनर्प्राप्ति में जा सके तथा वे -

- i. परमाण्विक एवं अन्य भारी धातुओं से उभरे प्रजासौ को समन्वित करेंगे
- ii. यदि अनुरोध किया जाए तो सहायता उपलब्ध करायेंगे;
- iii. परमाण्विक कार्गोईयों के माध्यम से यात्रा शुरू या खोये हुए नाभिकीय पदार्थ की वापसी को सुनिश्चित करेंगे ।

इस सहयोग के क्रियान्वयन के साधनों के बारे में संबंधित पक्षकार राज्यों द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।

3. नाभिकीय पदार्थ या किसी नाभिकीय सुविधा के तोड़फोड़ के विश्वसनीय खतरे या उनके तोड़फोड़ के मामले में, पक्षकार राज्य अपने राष्ट्रीय कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने सुसंगत बाध्यताओं के अनुरूप अधिकतम संभव सीमा तक निम्न रूप में सहयोग करेंगे:

(क) यदि एक पक्षकार राज्य को किसी दूसरे राज्य में नाभिकीय पदार्थ या नाभिकीय सुविधा के तोड़फोड़ के खतरे की विश्वसनीय जानकारी है तो वह राज्य उस राज्य को इस तोड़फोड़ को रोकने की दृष्टि से यथाशीघ्र इसकी सूचना प्रदान करने हेतु समुचित कदम उठावेगा तथा जहां उचित हो वह इस खतरे की सूचना अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एवं अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को देगा ।

(ख) एक पक्षकार राज्य में नाभिकीय पदार्थ या किसी नाभिकीय सुविधा के तोड़फोड़ के मामले में यदि उसका यह विचार हो कि इससे अन्य राज्य भी इससे विकिरणकीय रूप से प्रभावित हो सकते हैं तो वह

अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपनी अन्य बाध्यताओं को पूरा करते हुए यथाशीघ्र इसकी सूचना विकिरणकीय रूप से प्रभावित होने वाले संभावित राज्य या राज्यों को देने हेतु समुचित कदम उठायेगा और जहां उचित हो इसके विकिरणकीय परिणामों को कम करने या उनके शमन की दृष्टि से इसकी सूचना अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और अन्य संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को देगा।

(ग) यदि उप पैराग्राफ (क) एवं (ख) के प्रसंग में कोई पक्षकार राज्य सहायता का अनुरोध करता है तो वह प्रत्येक पक्षकार राज्य जिससे ऐसी सहायता का अनुरोध किया जाता है तत्काल इस संबंध में निर्णय लेगा तथा अनुरोध करने वाले पक्षकार राज्य को सीधे या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के माध्यम से इसकी सूचना देगा कि क्या वह अनुरोध की गई सहायता प्रदान करने की स्थिति में है तथा वह दी जाने वाली सहायता के क्षेत्र एवं शर्तों की सूचना भी उसे देगा।

(घ) उप पैराग्राफ (क) से (ग) के अंतर्गत सहयोग का समन्वय परस्पर सहमति से तय किये गये राजनयिक या अन्य माध्यमों द्वारा किया जाएगा। इस सहयोग के क्रियान्वयन के साधनों का अभिनिर्धारण द्विपक्षीय या बहुपक्षीय रूप से संबंधित पक्षकार राज्यों द्वारा किया जाएगा।

4. पक्षकार राज्य यथोचित रूप में एक-दूसरे के साथ सीधे या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से सहयोग एवं परामर्श करेंगे ताकि अंतर्राष्ट्रीय परिवहन में नाभिकीय पदार्थ के भौतिक संरक्षण की प्रणाली के अभिकल्प अनुरक्षण एवं विकास के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके।

5. एक पक्षकार राज्य घरेलू उपयोग, संयंत्रण एवं परिवहन में नाभिकीय पदार्थों तथा नाभिकीय सुविधाओं के भौतिक संरक्षण की राष्ट्रीय प्रणाली के अभिकल्प, अनुरक्षण एवं सुधार के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु सीधे या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से अन्य पक्षकार राज्यों से समुचित परामर्श एवं सहयोग कर सकता है।

8. इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 6 के स्थान पर निम्नलिखित पाठ रखा जाता है;

1. पक्षकार राज्य अपने राष्ट्रीय कानून के अनुरूप इस समझौते के प्रावधानों के अंतर्गत दूसरे पक्षकार राज्य से या इस समझौते के क्रियान्वयन के लिए की गई किसी कार्यवाई में सहभागिता के माध्यम से प्राप्त किसी गोपनीय सूचना की गोपनीयता को रक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाएंगे। यदि पक्षकार राज्य उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या राज्यों को सूचना उपलब्ध कराते हैं तो ऐसी सूचना की गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जाएंगे ताकि उसकी रक्षा की जा सके। एक पक्षकार राज्य जिसने दूसरे राज्य से गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त की है, तीसरे पक्षकारों को वह सूचना उस दूसरे पक्षकार राज्य के परामर्श से ही उपलब्ध करा सकता है।

इस कानून के अंतर्गत प्रत्येक राज्य से ऐसी सूचनाएं देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जिनको राष्ट्रीय कानून के अनुसार बताने की आवश्यकता नहीं है या जिनके कारण संबंधित राज्य या नाभिकीय पदार्थ या नाभिकीय सुविधाओं के भौतिक संरक्षण की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है ।

इस कानून के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 1 के स्थान पर निम्नलिखित पाठ रखा जाता है :

साभिप्राय किये गये कार्य में निम्नलिखित शामिल है :

- (क) बिना कानूनी प्राधिकार के नाभिकीय पदार्थ की प्राप्ति, उसे अपने कब्जे में रखना, उसका उपयोग, हस्तांतरण, रूपांतरण, निपटान या विसरण करना और उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु होना या उसे गहरी क्षति पहुंचना या इसकी संभावना या किसी संपत्ति या पर्यावरण को उल्लेखनीय रूप से नुकसान पहुंचना;
- (ख) नाभिकीय पदार्थ की चोरी या डकैती;
- (ग) नाभिकीय पदार्थ का गबन या उसे कपटपूर्ण ढंग से प्राप्त करना;
- (घ) बिना किसी कानूनी प्राधिकार के नाभिकीय पदार्थ को किसी राज्य में उससे बाहर ले जाने, भेजने या हटाने का कार्य ;
- (ङ) किसी नाभिकीय सुविधा के विरुद्ध निर्देशित या किसी नाभिकीय सुविधा के प्रचालन में हस्तक्षेप करने का कार्य जबकि अपराधी साभिप्राय या यह जानते हुए कि विकिरण के उद्भासन या विकिरण सक्रिय पदार्थों की निर्मुक्ति के उसके कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसको गंभीर रूप से क्षति पहुंच सकती है या किसी संपत्ति या पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंच सकता है, जब तक कि वह कार्य उस पक्षकार राज्य के राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं किया जाता है जिसके प्रदेश में वह नाभिकीय सुविधा स्थित है;
- (च) धमकी या बल प्रयोग या अन्य किसी रूप से डरा धमकाकर नाभिकीय पदार्थ की मांग करने का कार्य;
- (छ)
 - (i.) किसी व्यक्ति को मारने या गंभीर रूप से क्षति पहुंचाने या किसी संपत्ति या पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने हेतु नाभिकीय पदार्थ के उपयोग या उप पैराग्राफ (ङ) में वर्णित अपराध करने या
 - (ii.) उप पैराग्राफ (ख) एवं (ङ) में वर्णित कोई ऐसा अपराध करने की धमकी देना जिसे एक स्वाभाविक या कानूनी व्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या राज्य को कोई कार्रवाई करने या वैसा करने से विरत रहने के लिए बाध्य किया जा सके ।

- (ज) उप पैराग्राफ (क) से (ड) में वर्णित कोई अपराध करने का प्रयास करना तथा
- (झ) उप पैराग्राफ (क) से (ज) में वर्णित किसी अपराध में शामिल होने के किसी कार्य को
- (ञ) किसी व्यक्ति द्वारा उप पैराग्राफ (क) से (ज) में वर्णित किसी अपराध को करने हेतु दूसरों को संगठित या निर्देशित करने हेतु किया गया कोई कार्य तथा
- (ट) व्यक्तियों के एक समूह द्वारा सामान्य प्रयोजन से उप पैराग्राफ (क) से (ज) में वर्णित किसी अपराध को करने में दिए गए किसी प्रकार के सहयोग; ऐसी कार्य साभिप्राय किया गया माना जाएगा और यह कार्य या तो
- (i) समूह के अपराधिक गतिविधियों या अपराध को बढ़ाने के लिए किया जाएगा जिसमें इन गतिविधियों में या प्रयोजनों में उप पैराग्राफ (क) से (झ) में वर्णित अपराधों को अंजाम देना शामिल होगा या
- (ii) उप पैराग्राफ (क) से (झ) में वर्णित अपराधों को करने के लिए समूह के इरादों के लिए जानकारी में लाया जाएगा जो प्रत्येक पक्षकार राज्य द्वारा अपने राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंडनीय अपराध बनाया जाएगा ।

10 इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 11 के उपरांत अनुच्छेद 11 क एवं अनुच्छेद 11ख दो नए अनुच्छेदों को निम्न रूप में जोड़ा जाता है :

अनुच्छेद 11क

अनुच्छेद 7 में निर्धारित किसी भी अपराध को प्रत्यर्पण या परस्पर कानूनी सहायता के प्रयोजन हेतु राजनीतिक अपराध या राजनीतिक अपराध से संबंधित अपराध या राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित अपराध के रूप में नहीं माना जाएगा। तदनुसार ऐसे अपराध के आधार पर प्रत्यर्पण या परस्पर कानूनी सहायता के किसी अनुरोध को केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि वह राजनीतिक अपराध या राजनीतिक अपराध से संबंधित अपराध या राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित अपराध है।

अनुच्छेद 11ख

इस कन्वेंशन में किसी बात का निर्वचन इस रूप में नहीं किया जाएगा जो प्रत्यर्पण या परस्पर कानूनी सहायता के लिए ऐसे किसी राज्य को बाध्य करता है जिससे इसका अनुरोध किया गया है और उस पक्षकार राज्य के पास इस बात के पर्याप्त आधार हैं कि अनुच्छेद 7 के अंतर्गत निर्धारित अपराधों हेतु या परस्पर कानूनी सहायता हेतु ऐसे अपराधों के संबंध में किए गए प्रत्यर्पण का अनुरोध इस प्रयोजन हेतु किया गया है कि उस व्यक्ति को उस प्रजाति, धर्म, राष्ट्रीयता, जातीय मूल या राजनीतिक विचारधारा के आधार पर अभियोजित या दंडित किया जाए या उस अनुरोध के अनुपालन से इनमें से किन्हीं कारणों से उस व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

11. इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 13क के उपरांत एक नया अनुच्छेद निम्न रूप में जोड़ा जाता है :

अनुच्छेद 13क

इस कन्वेंशन का कोई भी अंश शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु ऐसी नाभिकीय प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को प्रभावित नहीं करेगा जो नाभिकीय पदार्थ एवं नाभिकीय सुविधाओं के भौतिक संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए की जा रही है।

12. इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 14 के पैराग्राफ 3 के स्थान पर निम्नलिखित पाठ रखा जाता है :

यदि कोई ऐसा अपराध होता है जिसमें घरेलू उपयोग, भंडारण या परिवहन में शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु नाभिकीय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है तथा कथित अपराधी एवं नाभिकीय पदार्थ उस पक्षकार राज्य के क्षेत्र में ही विद्यमान है जिसमें अपराध हुआ है या वहां कोई अपराध नाभिकीय सुविधा के संबंध में हुआ है तथा अभिकथित अपराधी उस पक्षकार राज्य के क्षेत्र में ही विद्यमान है जिसमें अपराध हुआ है तो इस समझौते में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका निर्वचन ऐसे अपराध के फलस्वरूप की जाने वाली आपराधिक कार्यवाहियों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के लिए पक्षकार राज्य को बाध्य करने के लिए किया जाए।

13. इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 16 के स्थान पर निम्नलिखित पाठ रखा जाता है

1. दिनांक 8 जुलाई 2005 को अंगीकार किए गए संशोधन के लागू होने के पांच वर्षों के उपरांत इस कन्वेंशन के क्रियान्वयन एवं इसकी प्रस्तावना की पर्याप्तता, इसके सभी प्रचालनात्मक अंग एवं परिशिष्टों की उस समय वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में पुनर्विलोकन के लिए पक्षकार राज्यों का एक सम्मेलन बुलाया जाएगा।
2. इसके उपरांत कम से कम पांच वर्षों के अंतराल पर पक्षकार राज्यों के बहुमत द्वारा इस संबंध में निक्षेपक (डिपोजिटरी) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर इसी उद्देश्य से आगे सम्मेलनों का आयोजन किया जा सकता है।

14. इस कन्वेंशन के परिशिष्ट II के फुट नोट बी/ के स्थान पर निम्नलिखित पाठ रखा जाता है :

बी/ रिएक्टर में किरणित पदार्थ या रिएक्टर में अकिरणित पदार्थ, लेकिन 1 मीटर की अपरिरक्षित दूरी पर 1 ग्रे प्रतिघंटे (100 रैड्स/प्रतिघंटे) के बराबर या उससे कम स्तर के विकिरण सहित

15. इस कन्वेंशन के परिशिष्ट II के फुट नोट ई/ के स्थान पर निम्नलिखित पाठ रखा जाता है :

1 मीटर की अपरिरक्षित दूरी पर 1 ग्रे प्रतिघंटे (100 रैड्स/प्रतिघंटे) से विकिरण स्तर बढ़ने पर किरणन के एक श्रेणी स्तर कम हो जाने से पूर्व अन्य ईंधन को मूल विखंडनीय पदार्थ के अंश के कारण श्रेणी-I एवं श्रेणी-II में रखा जाता है।

अतः अब भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि अध्याय III से भिन्न उक्त अधिनियम के प्रावधान इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी रूप में कन्वेंशन के पक्षकार राज्यों के लिए कन्वेंशन में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में लागू होंगे।

[फा. सं. टी 413/45/2009]

ए. मणिकम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(CPV Division)

ORDER

New Delhi, the 12th February, 2010

G.S.R. 168(E).—Whereas India is a State Party to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material 1980 having deposited the Instrument of Accession on 12th March 2002. The Convention came into force for India on 11 April, 2002. India has also ratified Amendment of 2005 to the Convention on 19th September, 2007;

WHEREAS Article 7 of the Convention sets forth certain acts as criminal offences and obliges the States Parties to make them punishable under their national law;

WHEREAS Article 8.1 requires the States Parties to establish jurisdiction over those offences;

WHEREAS according to Article 11 those offences are deemed to be included as extraditable in all existing and future extradition treaties of States parties;

WHEREAS in the absence of a bilateral extradition treaty between States Parties, the Convention provides a legal basis for extradition in respect of the offences set forth therein;

WHEREAS sub-section (4) of Section 3 of the Indian Extradition Act 1962 provides as follows: "Where there is no extradition treaty made by India with any foreign State, the Central Government may, by notified order, treat any convention to which India and a foreign State are parties, as an extradition treaty made by India with that foreign State providing for extradition in respect of the offences specified in that convention."

WHEREAS the text of the Convention and Amendment are annexed hereunder;

ANNEX:

THE CONVENTION ON THE PHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL

THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION,

RECOGNIZING the right of all States to develop and apply nuclear energy for peaceful purposes and their legitimate interests in the potential benefits to be derived from the peaceful application of nuclear energy,

CONVINCED of the need for facilitating international co-operation in the peaceful application of nuclear energy,

DESIRING to avert the potential dangers posed by the unlawful taking and use of nuclear material,

CONVINCED that offences relating to nuclear material are a matter of grave concern and that there is an urgent need to adopt appropriate and effective measures to ensure the prevention, detection and punishment of such offences,

AWARE OF THE NEED FOR international co-operation to establish, in conformity with the national law of each State Party and with this Convention, effective measures for the physical protection of nuclear material,

CONVINCED that this Convention should facilitate the safe transfer of nuclear material, STRESSING also the importance of the physical protection of nuclear material in domestic use, storage and transport,

RECOGNIZING the importance of effective physical protection of nuclear material used for military purposes, and understanding that such material is and will continue to be accorded stringent physical protection,

HAVE AGREED as follows:

Article 1

For the purposes of this Convention:

- a. "nuclear material" means plutonium except that with isotopic concentration exceeding 80% in plutonium-238; uranium-233; uranium enriched in the isotope 235 or 233; uranium containing the mixture of isotopes as occurring in nature other than in the form of ore or ore-residue; any material containing one or more of the foregoing;
- b. "uranium enriched in the isotope 235 or 233" means uranium containing the isotope 235 or 233 or both in an amount such that the abundance ratio of the sum of these isotopes to the isotope 238 is greater than the ratio of the isotope 235 to the isotope 238 occurring in nature;
- c. "international nuclear transport" means the carriage of a consignment of nuclear material by any means of transportation intended to go beyond the territory of the State where the shipment originates beginning with the departure from a facility of the shipper in that State and ending with the arrival at a facility of the receiver within the State of ultimate destination.

Article 2

1. This Convention shall apply to nuclear material used for peaceful purposes while in international nuclear transport.
2. With the exception of articles 3 and 4 and paragraph 3 of article 5, this Convention shall also apply to nuclear material used for peaceful purposes while in domestic use, storage and transport.

3. Apart from the commitments expressly undertaken by States Parties in the articles covered by paragraph 2 with respect to nuclear material used for peaceful purposes while in domestic use, storage and transport, nothing in this Convention shall be interpreted as affecting the sovereign rights of a State regarding the domestic use, storage and transport of such nuclear material.

Article 3

Each State Party shall take appropriate steps within the framework of its national law and consistent with international law to ensure as far as practicable that, during international nuclear transport, nuclear material within its territory, or on board a ship or aircraft under its jurisdiction insofar as such ship or aircraft is engaged in the transport to or from that State, is protected at the levels described in Annex I.

Article 4

1. Each State Party shall not export or authorize the export of nuclear material unless the State Party has received assurances that such material will be protected during the international nuclear transport at the levels described in Annex I.
2. Each State Party shall not import or authorize the import of nuclear material from a State not party to this Convention unless the State Party has received assurances that such material will during the international nuclear transport be protected at the levels described in Annex I.
3. A State Party shall not allow the transit of its territory by land or internal waterways or through its airports or seaports of nuclear material between States that are not parties to this Convention unless the State Party has received assurances as far as practicable that this nuclear material will be protected during international nuclear transport at the levels described in Annex I.
4. Each State Party shall apply within the framework of its national law the levels of physical protection described in Annex I to nuclear material being transported from a part of that State to another part of the same State through international waters or airspace.
5. The State Party responsible for receiving assurances that the nuclear material will be protected at the levels described in Annex I according to paragraphs 1 to 3 shall identify and inform in advance States which the nuclear material is expected to transit by land or internal waterways, or whose airports or seaports it is expected to enter.

6. The responsibility for obtaining assurances referred to in paragraph 1 may be transferred, by mutual agreement, to the State Party involved in the transport as the importing State.

7. Nothing in this article shall be interpreted as in any way affecting the territorial sovereignty and jurisdiction of a State, including that over its airspace and territorial sea.

Article 5

1. States Parties shall identify and make known to each other directly or through the International Atomic Energy Agency their central authority and point of contact having responsibility for physical protection of nuclear material and for co-ordinating recovery and response operations in the event of any unauthorized removal, use or alteration of nuclear material or in the event of credible threat thereof.

2. In the case of theft, robbery or any other unlawful taking of nuclear material or of credible threat thereof, States Parties shall, in accordance with their national law, provide co-operation and assistance to the minimum feasible extent in the recovery and protection of such material to any State that so requests, in particular:

- a. a State Party shall take appropriate steps to inform as soon as possible other States, which appear to it to be concerned, of any theft, robbery or other unlawful taking of nuclear material or credible threat thereof and to inform, where appropriate, international organizations;
- b. as appropriate, the States Parties concerned shall exchange information with each other or international organizations with a view to protecting threatened nuclear material, verifying the integrity of the shipping container, or recovering unlawfully taken nuclear material and shall:
 - i. co-ordinate their efforts through diplomatic and other agreed channels;
 - ii. render assistance if requested;
 - iii. ensure the return of nuclear material stolen or missing as a consequence of the above-mentioned events.

The means of implementation of this co-operation shall be determined by the States Parties concerned.

3. States Parties shall co-operate and consult as appropriate, with each other directly or through international organizations, with a view to obtaining guidance on the design, maintenance and improvement of systems of physical protection of nuclear material in international transport.

Article 6

1. States Parties shall take appropriate measures consistent with their national law to protect the confidentiality of any information which they receive in confidence by virtue of the provisions of this Convention from another State Party or through participation in an activity carried out for the implementation of this Convention. If States Parties provide information to international organizations in confidence, steps shall be taken to ensure that the confidentiality of such information is protected.
2. States Parties shall not be required by this Convention to provide any information which they are not permitted to communicate pursuant to national law or which would jeopardize the security of the State concerned or the physical protection of nuclear material.

Article 7

1. The intentional commission of:
 - a. an act without lawful authority which constitutes the receipt, possession, use, transfer, alteration, disposal or dispersal of nuclear material and which causes or is likely to cause death or serious injury to any person or substantial damage to property;
 - b. a theft or robbery of nuclear material;
 - c. an embezzlement or fraudulent obtaining of nuclear material;
 - d. an act constituting a demand for nuclear material by threat or use of force or by any other form of intimidation;
 - e. a threat:
 - i. to use nuclear material to cause death or serious injury to any person or substantial property damage, or
 - ii. to commit an offence described in sub-paragraph (b) in order to compel a natural or legal person, international organization or State to do or to refrain from doing any act;
 - f. an attempt to commit any offence described in paragraphs (a), (b) or (c); and

- g. an act which constitutes participation in any offence described in paragraphs (a) to (f)

shall be made a punishable offence by each State Party under its national law.

2. Each State Party shall make the offences described in this article punishable by appropriate penalties which take into account their grave nature.

Article 8

1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 7 in the following cases;

- a. when the offence is committed in the territory of that State or on board a ship or aircraft registered in that State;
- b. when the alleged offender is a national of that State.

2. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over these offences in cases where the alleged offender is presented in its territory and it does not extradite him pursuant to article 11 to any of the States mentioned in paragraph 1.

3. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with national law.

4. In addition to the States Parties mentioned in paragraphs 1 and 2, each State Party may, consistent with international law, establish its jurisdiction over the offences set forth in article 7 when it is involved in international nuclear transport as the exporting or importing State.

Article 9

Upon being satisfied that the circumstances so warrant, the State Party in whose territory the alleged offender is present shall take appropriate measures, including detention, under its national law to ensure his presence for the purpose of prosecution or extradition. Measures taken according to this article shall be notified without delay to the States required to establish jurisdiction pursuant to article 8 and, where appropriate, all other States concerned.

Article 10

The State Party in whose territory the alleged offender is present shall, if it does not extradite him, submit, without exception whatsoever and without undue delay, the case to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.

Article 11

1. The offences in article 7 shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between States Parties. States Parties undertake to include those offences as extraditable offences in every future extradition treaty to be concluded between them.

2. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may at its option consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of those offences. Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize those offences as extraditable offences between themselves subject to the conditions provided by the law of the requested State.

4. Each of the offences shall be treated, for the purpose of extradition between States Parties, as if it had been committed not only in the place in which it occurred but also in the territories of the States Parties required to establish their jurisdiction in accordance with paragraph 1 of article 8.

Article 12

Any person regarding whom proceedings are being carried out in connection with any of the offences set forth in article 7 shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings.

Article 13

1. States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal proceedings brought in respect of the offences set forth in article 7, including the supply of evidence at their disposal necessary for the proceedings. The law of the State requested shall apply in all cases.

2. The provisions of paragraph 1 shall not affect obligations under any other treaty, bilateral or multilateral, which governs or will govern, in whole or in part, mutual assistance in criminal matters.

Article 14

1. Each State Party shall inform the depositary of its laws and regulations which give effect to this Convention. The depositary shall communicate such information periodically to all States Parties.
2. The State Party where an alleged offender is prosecuted shall, wherever practicable, first communicate the final outcome of the proceedings to the States directly concerned. The State Party shall also communicate the final outcome to the depositary who shall inform all States.
3. Where an offence involves nuclear material used for peaceful purposes in domestic use, storage or transport, and both the alleged offender and the nuclear material remain in the territory of the State Party in which the offence was committed, nothing in this Convention shall be interpreted as requiring that State Party to provide information concerning criminal proceedings arising out of such an offence.

Article 15

The Annexes constitute an integral part of this Convention.

Article 16

1. A conference of States Parties shall be convened by the depositary of five years after the entry into force of this Convention to review the implementation of the Convention and its adequacy as concerns the preamble, the whole of the operative part and the annexes in the light of the then prevailing situation.
2. At intervals of not less than five years thereafter, the majority of States Parties may obtain, by submitting a proposal to this effect to the depositary, the convening of further conferences with the same objective.

Article 17

1. In the event of a dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention, such States Parties shall consult with a view to the settlement of the dispute by negotiation, or by any other peaceful means of settling disputes acceptable to all parties to the dispute.

2. Any dispute of this character which cannot be settled in the manner prescribed in paragraph 1 shall, at the request of any party to such dispute, be submitted to arbitration or referred to the International Court of Justice for decision. Where a dispute is submitted to arbitration, if, within six months from the date of the request, the parties to the dispute are unable to agree on the organization of the arbitration, a party may request the President of the International Court of Justice or the Secretary-General of the United Nations to appoint one or more arbitrators. In case of conflicting requests by the parties to the dispute, the request to the Secretary-General of the United Nations shall have priority.
3. Each State Party may at the time of signature, ratification, acceptance or approval of this Convention or accession thereto declare that it does not consider itself bound by either or both of the dispute settlement procedures provided for in paragraph 2. The other States Parties shall not be bound by a dispute settlement procedure provided for in paragraph 2, with respect to a State Party which has made a reservation to that procedure.
4. Any State Party which has made a reservation in accordance with paragraph 3 may at any time withdraw that reservation by notification to the depositary.

Article 18

1. This Convention shall be open for signature by all States at the Headquarters of the International Atomic Energy Agency in Vienna and at the Headquarters of the United Nations in New York from 3 March 1980 until its entry into force.
2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States.
3. After its entry into force, this Convention will be open for accession by all States.
 - a. This Convention shall be open for signature or accession by international organizations and regional organizations of an integration or other nature, provided that any such organization is constituted by sovereign States and has competence in respect of the negotiation, conclusion and application of international agreements in matters covered by this Convention.
 - b. In matters within their competence, such organizations shall, on their own behalf, exercise the rights and fulfil the responsibilities which this Convention attributes to States Parties.
 - c. When becoming party to this Convention such an organization shall communicate to the depositary a declaration indicating which States are members thereof and which articles of this Convention do not apply to it.

- d. Such an organization shall not hold any vote additional to those of its Member States.

5. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with depositary.

Article 19

1. This Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the twenty-first instrument of ratification, acceptance or approval with the depositary.

2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to the Convention after the date of deposit of the twenty-first instrument of ratification, acceptance or approval, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after the deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 20

1. Without prejudice to article 16 a State Party may propose amendments to this Convention. The proposed amendment shall be submitted to the depositary who shall circulate it immediately to all States Parties. If a majority of States Parties request the depositary to convene a conference to consider the proposed amendments, the depositary shall invite all States Parties to attend such a conference to be held not sooner than thirty days after the invitations are issued. Any amendment adopted at the conference by a two-thirds majority of all States Parties shall be promptly circulated by the depositary to all States Parties.

2. The amendment shall enter into force for each State Party that deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of the amendment on the thirtieth day after the date on which two thirds of the States Parties have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval with the depositary. Thereafter, the amendment shall enter into force for any other State Party on the day on which that State Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of the amendment.

Article 21

1. Any State Party may denounce this Convention by written notification to the depositary.

2. Denunciation shall take effect one hundred and eighty days following the date on which notification is received by the depositary.

Article 22

The depositary shall promptly notify all States of:

- a. each signature of this Convention;
- b. each deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c. any reservation or withdrawal in accordance with article 17;
- d. any communication made by an organization in accordance with paragraph 4(c) of article 18;
- e. the entry into force of this Convention;
- f. the entry into force of any amendment to this Convention; and
- g. any denunciation made under article 21.

Article 23

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Director General of the International Atomic Energy Agency who shall send certified copies thereof to all States.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized, have signed this Convention, opened for signature at Vienna and at New York on 3 March 1980.

Annex I

Levels of Physical Protection to be Applied in International Transport of Nuclear Materials as Categorized in Annex II

1. Levels of physical protection for nuclear material during storage incidental to international nuclear transport include:

- a. For Category III materials, storage within an area to which access is controlled;
- b. For Category II materials, storage within an area under constant surveillance by guards or electronic devices, surrounded by a physical barrier with a limited number of points of entry under appropriate control or any area with an equivalent level of physical protection;
- c. For Category I material, storage within a protected area as defined for Category II above, to which, in addition, access is restricted to persons whose trustworthiness has been determined, and which is under surveillance by guards who are in close communication with appropriate response forces. Specific measures taken in this context should have as

their object the detection and prevention of any assault, unauthorized access or unauthorized removal of material.

2 Levels of physical protection for nuclear material during international transport include:

- a. For Category II and III materials, transportation shall take place under special precautions including prior arrangements among sender, receiver, and carrier, and prior agreement between natural or legal persons subject to the jurisdiction and regulation of exporting and importing States, specifying time, place and procedures for transferring transport responsibility;
- b. For Category I materials, transportation shall take place under special precautions identified above for transportation of Category II and III materials, and in addition, under constant surveillance by escorts and under conditions which assure close communication with appropriate response forces;
- c. For natural uranium other than in the form of ore or ore-residue; transportation protection for quantities exceeding 500 kilograms uranium shall include advance notification of shipment specifying mode of transport, expected time of arrival and confirmation of receipt of shipment.

Annex II

Table: Categorization of Nuclear Material

Material	Form	Category		
		I	II	III ^d
1. Plutonium ^{a/}	Unirradiated ^{b/}	2 kg or more	Less than 2 kg but more than 500 g	500 g or less but more than 15 g
2. Uranium-235	Unirradiated ^{b/}	5 kg or more	Less than 5 kg but more than 1 kg	1 kg or less but more than 15 g
	<ul style="list-style-type: none"> uranium enriched to 20% ²³⁵U or more uranium enriched to 10% ²³⁵U but less than 20% uranium enriched above natural, but less than 10% ²³⁵U 		10 kg or more	Less than 10 kg but more than 1 kg
				10 kg or more
3. Uranium-233	Unirradiated ^{b/}	2 kg or more	Less than 2 kg but more than 500 g	500 g or less but more than 15 g
4. Irradiated fuel			Depleted or natural uranium, thorium or low-enriched fuel (less than 10% fissile content) ^{d/e/}	

- ^{a/} All plutonium except that with isotopic concentration exceeding 80% in plutonium-238.
- ^{b/} Material not irradiated in a reactor or material irradiated in a reactor but with a radiation level equal to or less than 100 rads/hour at one metre unshielded.
- ^{c/} Quantities not falling in Category III and natural uranium should be protected in accordance with prudent management practice.
- ^{d/} Although this level of protection is recommended, it would be open to States, upon evaluation of the specific circumstances, to assign a different category of physical protection.
- ^{e/} Other fuel which by virtue of its original fissile material content is classified as Category I and II before irradiation may be reduced one category level while the radiation level from the fuel exceeds 100 rads/hour at one metre unshielded.

Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material

1. The Title of the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material adopted on 26 October 1979 (hereinafter referred to as "the Convention") is replaced by the following title:

CONVENTION ON THE PHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL AND NUCLEAR FACILITIES

2. The Preamble of the Convention is replaced by the following text:

THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION,

RECOGNIZING the right of all States to develop and apply nuclear energy for peaceful purposes and their legitimate interests in the potential benefits to be derived from the peaceful application of nuclear energy,

CONVINCED of the need to facilitate international co-operation and the transfer of nuclear technology for the peaceful application of nuclear energy,

BEARING IN MIND that physical protection is of vital importance for the protection of public health, safety, the environment and national and international security,

HAVING IN MIND the purposes and principle's of the Charter of the United Nations concerning the maintenance of international peace and security and the promotion of good neighborliness and friendly relations and co-operation among States,

CONSIDERING that under the terms of paragraph 4 of Article 2 of the Charter of the United Nations, "All members shall refrain in their international relations

from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations,"

RECALLING the Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism, annexed to General Assembly resolution 49/60 of 9 December 1994,

DESIRING to avert the potential dangers posed by illicit trafficking, the unlawful taking and use of nuclear material and the sabotage of nuclear material and nuclear facilities, and noting that physical protection against such acts has become a matter of increased national and international concern,

DEEPLY CONCERNED by the worldwide escalation of acts of terrorism in all its forms and manifestations, and by the threats posed by international terrorism and organized crime,

BELIEVING that physical protection plays an important role in supporting nuclear non-proliferation and counter-terrorism objectives,

DESIRING through this Convention to contribute to strengthening worldwide the physical protection of nuclear material and nuclear facilities used for peaceful purposes,

CONVINCED that offences relating to nuclear material and nuclear facilities are a matter of grave concern- and that there is an urgent need to adopt appropriate and effective measures, or to strengthen existing measures, to ensure the prevention, detection and punishment of such offences,

DESIRING to strengthen further international co-operation to establish, in conformity with the national law of each State Party and with this Convention, effective measures for the physical protection of nuclear material and nuclear facilities,

CONVINCED that this Convention should complement the safe use, storage and transport of nuclear material and the safe operation of nuclear facilities,

RECOGNIZING that there are internationally formulated physical protection recommendations that are updated from time to time which can provide guidance on contemporary means of achieving effective levels of physical protection,

RECOGNIZING also that effective physical protection of nuclear material and nuclear facilities used for military purposes is a responsibility of the State possessing such nuclear material and nuclear facilities, and understanding that such material and facilities are and will continue to be accorded stringent physical protection,

HAVE AGREED as follows:

3. In Article 1 of the Convention, after paragraph (c), two new paragraphs are added as follows:

(d) "nuclear facility" means a facility (including associated buildings and equipment) in which nuclear material is produced, processed, used, handled, stored or disposed of, if damage to or interference with such facility could lead to the release of significant amounts of radiation or radioactive material;

(e) "sabotage" means any deliberate act directed against a nuclear facility or nuclear material in use, storage or transport which could directly or indirectly endanger the health and safety of personnel, the public or the environment by exposure to radiation or release of radioactive substances.

4. After Article 1 of the Convention, a new Article 1 A is added as follows:

The purposes of this Convention are to achieve and maintain worldwide effective physical protection of nuclear material used for peaceful purposes and of nuclear facilities used for peaceful purposes; to prevent and combat offences relating to such material and facilities worldwide; as well as to facilitate cooperation among States Parties to those ends.

5. Article 2 of the Convention - replaced by the following text:

1. This Convention shall apply to nuclear material used for peaceful purposes in use, storage and transport and to nuclear facilities used for peaceful purposes, provided, however, that articles 3 and 4 and paragraph 4 of article 5 of this Convention shall only apply to such nuclear material while in international nuclear transport.

2. The responsibility for the establishment, implementation and maintenance of a physical protection regime within a State Party rests entirely with that State.

3. Apart from the commitments expressly undertaken by States Parties under this Convention, nothing in this Convention shall be interpreted as affecting the sovereign rights of a State.

4. (a) Nothing in this Convention shall affect other rights, obligations and responsibilities of States Parties under international law, in particular the purposes and principles of the Charter of the United Nations and international humanitarian law.

(b) The activities of armed forces during an armed conflict, as those terms are understood under international humanitarian law, which are governed by that law, are not governed by this Convention, and the activities undertaken by the military forces of a State in the exercise of their official duties, inasmuch as they are governed by other

rules of international law, are not governed by this Convention.

8166/10-6

(c) Nothing in this Convention shall be construed as a lawful' authorization to use or threaten to use force against nuclear material or nuclear facilities used for peaceful purposes.

d) Nothing in this Convention condones or makes lawful otherwise unlawful acts, nor precludes prosecution under other laws.

5. This Convention shall not apply to nuclear material used or retained for military purposes or to a nuclear facility containing such material.

6. After Article 2 of the Convention, a new Article 2A is added as follows:

Article 2A

1. Each State Party shall establish, implement and maintain an appropriate physical protection regime applicable to nuclear material and nuclear facilities under its jurisdiction, with the aim of :

(a) protecting against theft and other unlawful taking of nuclear material in, use, storage and transport;

(b) ensuring the implementation of rapid and comprehensive measures to locate and, where appropriate, recover missing or stolen nuclear material; when the material is located outside its territory, that State Party shall act in accordance with article 5;

(c) protecting nuclear material and nuclear facilities against sabotage; and

(d) mitigating or minimizing the radiological consequences of sabotage.

2. In implementing paragraph 1, each State Party shall:

(a) establish and maintain a legislative and regulatory framework to govern physical protection;

(b) establish or designate a competent authority or authorities responsible for the implementation of the legislative and regulatory framework; and

(c) take other appropriate measures necessary for the physical protection of nuclear material and nuclear facilities.

3. In implementing the obligations under paragraphs 1 and 2, each State Party shall, without prejudice to any other provisions of this Convention, apply insofar as is reasonable and practicable the following Fundamental Principles of Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE A: *Responsibility of the State*

The responsibility for the establishment, implementation and maintenance of a physical protection regime within a State rests entirely with that State.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE B: Responsibilities During International Transport

The responsibility of a State for ensuring that nuclear material is adequately protected extends to the international transport thereof, until that responsibility is properly transferred to another State, as appropriate.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE C: Legislative and Regulatory Framework

The State is responsible for establishing and maintaining a legislative and regulatory framework to govern physical protection. This framework should provide for the establishment of applicable physical protection requirements and include a system of evaluation and licensing or other procedures to grant authorization. This framework should include a system of inspection of Nuclear facilities and transport to verify compliance with applicable requirements and conditions of the license or other authorizing document, and to establish a means to enforce applicable requirements and conditions, including effective sanctions.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE D: Competent Authority

The State should establish or designate a competent authority which is responsible for the implementation of the legislative and regulatory framework, and is provided with adequate authority, competence and financial and human - resources to fulfill its assigned responsibilities. The State should take steps to ensure an effective independence between the functions of the State's competent authority and those of any other body in charge of the promotion or utilization of nuclear energy.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE E: Responsibility of the License Holders

The responsibilities for implementing the various elements of physical protection within a State should be clearly identified. The State should ensure that the prime responsibility for the implementation of physical protection of nuclear material or of nuclear facilities rests with the holders of the relevant licenses or of other authorizing documents (e.g., operators or shippers).

FUNDAMENTAL PRINCIPLE F: Security Culture

All organizations involved in implementing physical protection should give due priority, to the security culture, to its development and maintenance necessary to ensure its effective implementation in the entire organization.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE G: *Threat*

The State's physical protection should be based on the State's current evaluation of the threat.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE H: *Graded Approach*

Physical protection requirements should be based on a graded approach, taking into account the current evaluation of the threat, the relative attractiveness, the nature of the material and potential consequences associated with the unauthorized removal of nuclear material and with the sabotage against nuclear material or nuclear facilities.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE I: *Defence in Depth*

The State's requirements for physical protection should reflect a concept of several layers and methods of protection (structural or other technical, personnel and organizational) that have to be overcome or circumvented by an adversary, in order to achieve his objectives.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE J: *Quality Assurance*

A quality assurance policy and quality assurance programmes should be established and implemented with a view to providing confidence that specified requirements for all activities important to physical protection are satisfied.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE K: *Contingency Plans*

Contingency (emergency) plans to respond to unauthorized removal of nuclear material or sabotage of nuclear facilities or nuclear material, or attempts thereof, should be prepared and appropriately exercised by all

license holders and authorities concerned.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE L: *Confidentiality*

The State should establish requirements for protecting the confidentiality of information, the unauthorized disclosure of which could compromise the physical protection of nuclear material and nuclear facilities.

4. (a) The provisions of this article shall not apply to any nuclear material which the State Party reasonably decides does not need to be subject to the physical protection regime established pursuant to paragraph 1, taking into account the nature of the material, its quantity and relative attractiveness and the potential radiological and other consequences associated with any unauthorized act directed against it and the current evaluation of the threat against it.

(b) Nuclear material which is not subject to the provisions of this article pursuant to subparagraph (a) should be protected in accordance with prudent management practice.

7. Article 5 of the Convention is replaced by the following text:

1. States Parties shall identify and make known to each other directly or through the International Atomic Energy Agency their point of contact in relation to matters within the scope of this Convention.

2. In the case of theft, robbery or any other unlawful taking of nuclear material or credible threat thereof, States Parties shall, in accordance with their national law, provide co-operation and assistance to the maximum feasible extent in the recovery and protection of such material to any State that so requests. In particular:

(a) a State Party shall take appropriate steps to inform as soon as possible other States, which appear to it to be concerned, of any theft, robbery or other unlawful taking of nuclear material or credible threat thereof, and to inform, where appropriate, the International Atomic Energy Agency and other relevant international organizations;

(b) in doing so, as appropriate, the States Parties concerned shall exchange information with each other, the International Atomic Energy Agency and other relevant international organizations with a view to protecting threatened nuclear material, verifying the integrity of the shipping container or recovering unlawfully taken nuclear material and shall:

(i) co-ordinate their efforts through diplomatic and other agreed channels;

(ii) render assistance, if requested;

(iii) ensure the return of recovered nuclear material stolen or missing as a consequence of the above-mentioned events.

The means of implementation of this co-operation shall be determined by the States Parties concerned.

3. In the case of a credible threat *of* sabotage of nuclear material or a nuclear facility *or* in the case *of* sabotage thereof, States Parties shall, to the maximum feasible extent, in accordance with their national law and consistent with their relevant obligations under international law, cooperate as follows:

(a) if a State Party has knowledge of a credible threat of sabotage of nuclear material or a nuclear facility in another State, the former shall decide on appropriate steps to be taken in order to inform that State as soon as possible and, where appropriate, the International Atomic Energy Agency and other relevant international organizations of that threat, with a view to preventing the sabotage;

(b) in the case of sabotage of nuclear material or a nuclear facility in a State Party and if in its view other States are likely to be radiologically affected, the former, without prejudice to its other obligations under international law, shall take appropriate steps to inform as soon as possible the State or the States which are likely to be radiologically affected and to inform, where appropriate, the International Atomic Energy Agency and other relevant international organizations, with a view to minimizing or mitigating the radiological consequences thereof;

(c) if in the context of sub-paragraphs (a) and (b), a State Party requests assistance, each State Party to which a request *for* assistance is directed shall promptly decide and notify the requesting State Party, directly or through the International Atomic Energy Agency, whether it is in a position to render the assistance requested and the scope and terms of the assistance that may be rendered;

(d) co-ordination of the co-operation under sub-paragraphs (a) to (c) shall be through diplomatic or other agreed channels. The means of implementation of this cooperation shall be determined bilaterally or multilaterally by the States Parties concerned.

4. States Parties shall co-operate and consult, as appropriate, with each other directly or through the International Atomic Energy Agency and other relevant international organizations, with a view to obtaining guidance on the design, maintenance and improvement of systems of physical protection of nuclear material in international transport.

5. A State Party may consult and co-operate, as appropriate, with other States Parties directly or through the International Atomic Energy Agency and other relevant international organizations, with a view to obtaining their guidance on the design, maintenance and improvement of its national system of physical protection of nuclear material in domestic use, storage and transport and of nuclear facilities.

8. Article 6 of the Convention is replaced by the following text:

1. States Parties shall take appropriate measures consistent with their national law to protect the confidentiality of any information which they receive in confidence by virtue of the provisions of this Convention from another State Party or through participation in an activity carried out for the implementation of this Convention. If States Parties provide information to international organizations or to States that are not parties to this Convention in confidence, steps shall be taken to ensure that the confidentiality of such information is protected. A State Party that has received information in confidence from another State Party may provide this information to third parties only with the consent of that other State Party.

2. States Parties shall not be required by this Convention to provide any information which they are not permitted to communicate pursuant to national law or which would jeopardize the security of the State concerned or the physical protection of nuclear material or nuclear facilities.

9. Paragraph 1 of Article 7 of the Convention is replaced by the following text:

1. The intentional commission of:

(a) an act without lawful authority which constitutes the receipt, possession, use, transfer, alteration, disposal or dispersal of nuclear material and which causes or is likely to cause death or serious injury to any person or substantial damage to property or to the environment;

(b) a theft or robbery of nuclear material; .

(c) an embezzlement or fraudulent obtaining of nuclear material;

(d) an act which constitutes the carrying, sending, or moving of nuclear material into or out of a State without lawful authority;

(e) an act directed against a nuclear facility, or an act interfering with the operation of a nuclear facility, where the offender intentionally causes, or where he knows that the act is likely to cause, death or serious injury to any person or substantial damage to property or to the environment by exposure to radiation or release of radioactive substances, unless the act is undertaken in conformity with the national law of the State Party in the territory of which the nuclear facility is situated;

(f) an act constituting a demand *for* nuclear material by threat or use of force or by any other form of intimidation;

(g) a threat:

(i) to use nuclear material to cause death or serious injury to any person or substantial damage to property or to the environment or to commit the offence described in sub-paragraph (e), or

(ii) to commit an offence described in sub-paragraphs (b) and (e) in order to compel a natural or legal person, international organization or State to do or to refrain from doing any act;

(h) an attempt to commit any offence described in sub-paragraphs (a) to (e);

(i) an act which constitutes participation in any offence described in subparagraphs (a) to (h);

(j) an act of any person who organizes or directs others to commit an offence described in sub-paragraphs (a) to (h); and

(k) an act which contributes to the commission of any offence described in sub paragraphs (a) to (h) by a group of persons acting with a common purpose; such act shall be intentional and shall either:

- (i) be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, where such activity or purpose involves the commission of an offence described in sub-paragraphs(a) to (g), or
- (ii) be made in the knowledge of the intention of the group to commit an offence described in sub-paragraphs (a) to (g) shall be made a punishable offence by each State Party under its national law.

10. After Article 11 of the Convention, two new articles, Article 11A and Article 11B, are added as follows:

Article 11A

None of the offences set forth in article 7 shall be regarded *for* the purposes of extradition or mutual legal assistance, as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives. Accordingly, a request *for* extradition or for mutual legal assistance based on such an offence may not be refused on the sole ground that it concerns a political offence or an offence connected with a political offence or an offence inspired by political motives.

Article 11B

Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite or to afford mutual legal assistance, if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request for extradition for offences set forth in article 7 or for mutual legal assistance with respect to such offences has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin or political opinion or that compliance with the request would cause prejudice to that person's position for any of these reasons.

11. After Article 13 of the Convention, a new Article 13A is added as follows:

Article 13A

Nothing in this Convention shall affect the transfer of nuclear technology for peaceful purposes that is undertaken to strengthen the physical protection of nuclear material and nuclear facilities.

12. Paragraph 3 of Article 14 of the Convention is replaced by the following text:

Where an offence involves nuclear material in domestic use, storage or transport, and both the alleged offender and the nuclear material remain in the territory of the State Party in which the offence was committed, or where an offence involves a nuclear facility

and the alleged offender remains in the territory of the State Party in which the offence was committed, nothing in this Convention shall be interpreted as requiring that State Party to provide information concerning criminal proceedings arising out of such an offence,

13. Article 16 of the Convention is replaced by the following text:

1. A conference of States Parties shall be convened by the depositary five years after the entry into force of the Amendment adopted on 8 July, 2005 to review the implementation of this Convention and its adequacy as concerns the preamble, the whole of the operative part and the annexes in the light of the then prevailing situation.

2. At intervals of not less than five years thereafter, the majority of States Parties may obtain, by submitting a proposal to this effect to the depositary, the convening of further conferences with the same objective.

14. Footnote b/of Annex II of the Convention is replaced by the following text:

b/ Material not irradiated in a reactor or material irradiated in a reactor but with a radiation level equal to or less than 1 gray/hour (100 rads/hour) at one metre unshielded.

15. Footnote e/of Annex II of the Convention is replaced by the following text:

e/ Other fuel which by virtue of its original fissile material content is classified as Category I and II before irradiation may be reduced one category level while the radiation level from the fuel exceeds 1 gray/hour (100 rads/hour) at one metre unshielded.

Now therefore, in the exercise of the power conferred by sub-section 4 of Section 3 of the Indian Extradition Act 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to States Parties to the Convention with effect from the date of publication of this notification, in respect of the offences specified in the Convention.

[F. No.T 413/45/2009]
A. MANICKAM, Jt. Secy.